We are aware that there will be no representation from South Africa in Commonwealth Games but we cannot forget the overall effects of permitting apartheid in any field of sports. MCC is an important sports organisation. They themselves had in the past cancelled their South African tour because South Africa insisted that MCC should field only an all-white team. It is a matter for regret that they should have decided to invite South Africa to play a series of matches in U.K. and thus reversed their earlier decision and gone against the strong public opinion in their own country. It is all the more regrettable that they are inviting apartheid-practising South Africa to send a cricket team to play in the U.K. during the very year when South Africa has been excluded from the Commonwealth Games that will be played in the same country.

Government have decided that they should advise the Indian Olympic Association to inform the Commonwealth Games authorities that if the South African Cricket team's tour to U.K. is not abandoned, India will not participate in the Commonwealth Games. The I.O.A. is being advised accordingly.

RE-CALLING ATTENTION
(Query)

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Sir, yesterday we submitted a calling-attention notice in regard to the interim order passed by the Madras High Court. In that order the Madras High Court has ordered the Election Commission..... . *(Interruption)*

MR. SPEAKER : I received your calling-attention.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I am coming to another point.

In that order the Madras High Court has ordered the Election Commission not to issue instructions to the returning officer or the election officer of Tamil Nadu not to allot the bulls symbol to the Congress candidate of Tamil Nadu Congress Committee.

The Election Commissioner had intimated us the time-table for the bye-election to the Cheran Mahadevi Assembly Constituency in which the notification was to be issued yesterday, the nominations were to be filed up to 11th, the scrutiny was to be held on the 12th, the date of withdrawals was 14th and the date of election, if necessary, was 5th June. But today, they have sent another letter saying that the entire time-table intimated to us is being cancelled. This is something which is unusual.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): This is a serious contempt of the court. The Chief Election Commissioner should be asked to explain.

MR. SPEAKER : I will ask the Minister to make a statement.

DR. RAM SUBHAG SINGH: Let him make the statement in the afternoon.

SHRI KANWARLAL GUPTA: The Law Minister should make a statement on this. It is a serious contempt of the court.... *(Interruptions)*

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): May I make a submission?

MR. SPEAKER : No please. Even though I had not conveyed anything about my permission, your leader got up. Being the Leader of the opposition, I agreed with him. I will be sending it to the Minister to make a statement.

DR. RAM SUBHAG SINGH : The time may be fixed so that we might be present here.

MR. SPEAKER : I cannot say now without contacting him.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : This is a clear case of misuse of power. *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I am really at a loss to understand the way the things are going on in this Parliament. I may be wrong. But I see something in future which is very disappointing. *(Interruption)* I can tell you it is clearly written on the wall. *(Interruptions)* May I request you to please observe some silence?

FINANCE BILL, 1970—*contd.*

MR. SPEAKER : Now, we have a balance of 5 hours and 30 minutes for the General Discussion. So, the Prime Minister will reply at 5·30 P.M.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : The Prime Minister may reply at 6 O'Clock. you give us half an hour more.

MR. SPEAKER : You will differ with everything. God help you. You raise controversy about everything. (*Interruption*).

SHRI SHEO NARAIN: If you permit us, we will sit outside from tomorrow.... (*Interruption*)

MR. SPEAKER : I will very much welcome....(*Interruption*)

SHRI SHEO NARAIN : We are all Members of this House; we are elected Members....(*Interruption*)

MR. SPEAKER : You go on shouting.

SHRI SHEO NARAIN : This is not the way to treat the Members in this House.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : May I sit down so that you go on shouting for some more time?

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): There need not be any provocation from either side.

MR. SPEAKER : No provocation. (*Interruption*) There is no lunch hour today. So, you will have more time. The Prime Minister will reply at 5·30 P.M.

Shri Shiva Chandra Jha to continue his speech.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि अर्बन वैल्थ टैक्स, शहरी सम्पत्ति कर जिस रेट से लगाया जा रहा है, देखने से तो यह मालूम पड़ता है कि यह रेट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है । जैसा मैंने कहा था—जिसके पास 50 लाख की सम्पत्ति है, मौजूदा रेट से जो कर लगाया जायगा, उस से वह 1 लाख 99 हजार रुपये देकर छूट जायगा और इस तरह से उस के पास 48 लाख रुपया बच जायगा । अब जिस के पास 48 लाख रुपया बच जाता है, उस पर कितना बोझ पड़ा, हम अन्दाजा लगा सकते हैं । देखने में तो इस वित्त विधेयक से हम ऐसा महसूस करते हैं कि सम्पत्ति कर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में जिस के पास सम्पत्ति है, उस पर कोई बोझ नहीं पड़ा रहा है ।

अर्बन प्रोपर्टी में एक दूसरी बात यह है कि शहरों की जो विभिन्न कैटेगरीज पहले थीं, अब उन का खात्मा करने की बात हो रही है । पहले ए०बी०सी०डी०—शहरों की चार कैटेगरीज थीं, लेकिन अब इन में यूनीफोर्मिटी लाने के लिये पांच लाख तक के लिये एक आम रेट रखा जा रहा है । देखने में तो यह कदम बड़ा प्रोग्रेसिव मालूम पड़ता है कि छोटे शहर और बड़े शहर में भेद नहीं रहेगा, सब पर एक समान टैक्स लगेगा, लेकिन यदि इस के पीछे हम जाएं तो हमें मालूम हो जायगा कि एक हाथ से लिया जाता है तो दूसरे हाथ से कई लखपतियों को इससे छूट भी मिल रही है । अभी तक ए० बी० सिटीज़ में एक्जेम्प्शन लिमिट 4 लाख थी, लेकिन इस रेट के मुताबिक 5 लाख होने से उन की एक्जेम्पशन लिमिट ऊपर उठ जाती है, जिससे अनेकों लखपतियों को छूट मिल जाती है । सी० सिटीज में जिनकी, सम्पत्ति है, उन को तीन लाख की छूट है, लेकिन अब मौजूदा हिसाब से 5 लाख की छूट हो जाती है, इस तरह से ये लोग बेदाग़ निकल जाते हैं ।

13.18 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

डी० सिटीज में इस समय 2 लाख की एक्जेम्पशन लिमिट है, लेकिन अब 5 लाख की एक्जेम्पशन लिमिट होने से वे बेदाग निकल रहे हैं । देखने में तो यह मालूम पड़ता है कि छोटे शहरों को बड़े शहरों के मुकाबले ला कर बड़ी सम्पत्ति वालों को एक धागे में बांध रहे हैं, लेकिन हकीकत में बहुत से लखपति इससे बेदाग़ निकल जायेंगे । उन को इस वित्त विधेयक से राहत मिलती है ।

अर्बन प्रापर्टी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, जिस जगह 10 हजार की

आबादी है और 8 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र इस में शामिल किया जा रहा है। देखने से यह मालूम पड़ता है कि इस परिभाषा में उस के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो पूंजीपति यहां पर काम करते हैं, वे तो 30-30 मील दूर रहते हैं, 30 मील दूर से आ कर काम करते हैं, इस लिये 8 किलोमीटर की दूरी बहुत कम है, इस को ज्यादा करना चाहिये और इस के साथ ही जो 10 हजार की आबादी का एरिया इसमें किया जायगा, उस के बजाय 7 हजार की आबादी के एरिये को इस में लेना चाहिये।

दूसरी बात—अर्बन प्रापर्टी पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उस में इवेजन नहीं होगा, इस के बारे में प्रधान मंत्री जी क्या गारन्टी देती हैं। सरकार कौन सी गारन्टी देती है कि टैक्स इवेजन नहीं होगा और उसको रोकने के लिए इनके पास कौन सी मशीनरी है ? काल्डोर का कहना है कि अर्बन प्रापर्टी पर टैक्स के इवेजन को रोकने के लिए एक सेन्ट्रल मशीनरी की जरूरत है जिसके जरिए से इसको रोका जा सकता है लेकिन न तो बजट में और न फाइनन्स बिल में ही इस तरह की मशीनरी की कोई बात कही गई है। इसलिए टैक्स इवेजन की सम्भावना बहुत है।

जहां तक इनकम-टैक्स का सवाल है, 48 सौ से पांच हजार की एग्जेम्शन लिमिट कर दी गई है। इसके लिए दलील दी जा रही है कि चूंकि टैक्सपेयर की संख्या कम हो जायेगी इसलिए टैक्स इवेजन को रोकन में आसानी होगी। मैंने जैसाकि उस दिन भी कहा था कि यह बचकाना तर्क है, एक चाइल्डिश आर्गूमेन्ट है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जितने असेसीज हैं उनकी संख्या दो ही रह जाये तो और भी आसानी हो जायेगी ; इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मशीनरी का कितना ज्यादा दिवालियापन है। यह बात जरूर है कि पांच हजार की लिमिट कर देने से एन्टरप्राइजिंग नौजवान लोगों को जोकि महीने म 417 रुपया कमाते हैं उनको कुछ राहत मिलेगी और इसलिए मैं इस कदम का स्वागत कर सकता हूं।

उसी तरह से चैरिटेबिल और रेलिजस ट्रस्ट की बात है। रेलिजस ट्रस्ट की बात तो समझ में नहीं आती कि उसको छूट क्यों दी गई है। कुछ संशोधन भी इसके लिए लाये गए हैं लेकिन हकीकत में रेलिजस ट्रस्ट को कोई छूट देने की जरूर नहीं है। यूनिट ट्रस्ट से जो डिवीडेन्ड आता है उसपर अभी की छूट एक हजार है लेकिन अब वह छूट तीन हजार तक होने जा रही है। इसकी वजह से आज कारपोरेट सेक्टर फूले नहीं समा रहा है। इस सिलसिले में मैं पोलिटिकल ऐंड एकोनामिक वीकली से थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

The immediate cause for their exultation is the increase in the tax free limit for unearned income from Rs. 1,500 (Rs. 1,000 from unit trust units and Rs. 500 from dividends) to Rs. 3000 (from units and dividends). This should enable a man to own wealth upto Rs. 80,000 to Rs. 90,000 and live wholly on untaxed income by not working.

इस तरह से पैरासाइटों को बढ़ाने का एक तरीका रखा जाता है। उसी तरह से उसमें कहा गया है :

Stock Market is all Smiles: 3 Cheers for Indira: The stock market has cast off its slough of despondency and is all smiles now. Nobody ever thought that the radical Prime Minister could present a market oriented budget.

इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे डांडेकर साहब जो काम करना चाहते थे वही काम इस विधेयक से हो रहा है। इनकम-टैक्स में जहां

[श्री शिवचन्द्र झा]

पर छूट होनी चाहिए वहां पर तो है नहीं और जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर छूट दी गई है। इससे आम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है बल्कि ज्यादा इनकम वालों के फायदे की ही बात आती है। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, दोनों से ही टैक्स इवेजन की बात आती है और इस लूपहोल को प्लग करने के लिए कालडोर ने कहा है कि एक्सपेंडीचर टैक्स लगना चाहिए। उसको लगाया गया था लेकिन हटा दिया गया क्योंकि श्री मोरारजी भाई ने कहा कि उसमें कुछ आता नहीं है। और अब प्रधान मन्त्री भी उसी को फालो कर रही हैं। तो एक्सपेंडीचर टैक्स को लागू करना चाहिए। अगर आप यह कहते हैं कि उससे मिलता नहीं है तो मैं कहूंगा कि जो आपके कोलीग हैं उनसे भी दस साल तक आपको टैक्स नहीं मिला। यह सारी खराबी आपकी मशीनरी की है कि दस साल तक आप अपने बगल के कोलीग से भी टैक्स रियलाइज नहीं कर सके। अगर आप एक्सपेंडीचर टैक्स से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यह आपकी मशीनरी का दोष है।

गिफ्ट टैक्स में आप सख्ती करने जा रहे हैं, 10 हजार से पांच हजार पर लिए जा रहे हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि पांच हजार कौन लोग देते हैं और कितने लोग देते हैं। सफदरजंग में जितने लोग रहते हैं उनमें कितने पांच हजार का गिफ्ट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर। इसलिए उसकी सीमा और कम होनी चाहिए।...(**व्यवधान**)...

जहां तक 225 करोड़ के डेफिसिट फाइनेंसिंग का सवाल है, यह हिन्दुस्तान के बजट का एक पार्ट हो गया है। हिन्दुस्तान की कोई भी फैक्टरी अगर चौबीस घंटे चलती है तो वह है नासिक प्रेस। और उद्योगों में तो सुस्ती है लेकिन नोट छापने के लिए जो फैक्टरी है उसमें कोई सुस्ती नहीं है। मैं समझता हूं कि 225 करोड़ की ही बात नहीं है बल्कि इस रकम के और बढ़ने की बात है। किताब का कन्सेशन इन्होंने बताया। विद्यार्थियों की कलम, पेंसिल, औजार बक्स पर कन्सेशन की बात ठीक है लेकिन वह बहुत थोड़ी है। किताब पर कन्सेशन आपको कुछ ज्यादा देना चाहिए था।

बजट के वित्त विधेयक से ऐसा मालूम होता है कि टैक्जेशन की नालेज होने जा रही है...(**व्यवधान**)...मैं इसके खिलाफ नहीं हूं।...(**व्यवधान**)...मेरा कहना है कि रियायतें कम हैं वह और ज्यादा होनी चाहिए।...(**व्यवधान**)...कोल्ड स्टोरेज के पार्ट्स पर छूट देने का एलान किया गया है। ठीक है, यह तारीफ की बात है क्योंकि हिन्दुस्तान के जितने प्रोग्राम्स होते हैं और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं मोटे तौर पर वे कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं इसीलिए शायद उनका बढ़ना जरूरी है लेकिन प्रैगमेटिक दृष्टिकोण से कोल्ड स्टोरेज पर कोई छूट देने की जरूरत नहीं है।...(**व्यवधान**)...चाय के बारे में मैंने उस दिन निवेदन किया था। मेरा कहना है कि आप कानून तो बना सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं बना सकते हैं। इस देश का और समाज का तकाजा है कि हम इस विधेयक के जरिए या दूसरे विधेयकों के जरिए से केवल कानून ही न बनायें बल्कि इतिहास भी बनायें। वित्त विधेयक में सर्टेन फंडामेन्टल प्रिंसिपुल्स का समावेश होना चाहिए। इसमें आपको एक और दस के हिसाब पर इनकम पर सीलिंग लगाने की बात करनी चाहिए। 93 परसेन्ट देने के बाद भी लोगों के पास बहुत रह जाता है। आपको समाज में मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब करना होगा और उसी के हिसाब से टैक्जेशन करना होगा।...(**व्यवधान**)...चांसलर ऑफ एक्सचेकर ने कहा है कि टैक्जेशन का प्रिंसिपल यह नहीं है कि कितना आप पाते हैं बल्कि आप किस तरह से पाते हैं। उसी तरह से इसमें परिवर्तन करना होगा।...(**व्यवधान**)...दस हजार से ऊपर सर्कुलेशन के अखबारों को नेशनलाइज करना चाहिए और प्रीवी पर्स का खात्मा करना चाहिए। और इनकम सीलिंग एक और दस के रिशियो में मुस्तैदी से लागू करनी चाहिए तभी जाकर

हम कह सकते हैं कि इस विधेयक के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : The Prime Minister deserves congratulations on presenting a budget which aims at reducing inequalities, at reducing poverty, at enlarging exports, at taxing luxuries more heavily, which gives relief to the weaker sections of society by raising the exemption limit for taxation, by giving relief from taxation on necessities of life and which aims at the establishment of a socialist pattern of society. The budget aims at reducing inequalities by imposing taxation in the form of income-tax, wealth tax, gift tax, estate duty and using these revenues for the development of the nation for providing more avenues of employment by building public sector industries, by opening more social welfare schemes and so forth.

A theory has been propounded by some that we are the highest taxed nation, that the present budget imposes the maximum tax which is not found anywhere else in the world. My complaint, on the contrary, is that the taxation is very liberal; in fact, it does not tax to the extent or limit it should. Take, for example, estate duty. In Great Britain, the rate is heavier than here. Estate duty is one of those taxes which can bring more revenue and at the same time inflict the minimum pain on the tax-payer because it is levied on the death of the tax-payer. A heavy estate duty is also supported by our ancient mythology. One of our rishis was doing a lot of *tapas*. Then Lord Vishnu appeared before him and asked 'What do you want?' The rishi said: 'I want wealth which would last for generations'. Lord Vishnu asked: 'Why do you want wealth which would last for generations? For example, if you have a *kuputra* (a bad son), he will dissipate the wealth in a short time. If you have a *suputra* (good son), why do you need it? He will earn on his own. So either way you do not need wealth which would last for generations'.

My submission is that estate duty should operate with that object in view. Therefore, the rate of taxation should be raised to what it is in Great Britain at least.

So the theory that India is the highest taxed nation is, so far as estate duty is concerned, an exploded one.

Coming to income-tax, it is said that it is the highest when compared to the rates in the US and UK. I think our taxation is not very heavy. Not only this; we have completely left out the rural sector from agricultural income-tax. In fact, 80 per cent of India lives in villages and in that sector also there are wealthier sections who have plantations, gardens etc. and who own lakhs. There is no justification for leaving them out. The industrial section of the society is going in for large farms for the purpose of evading income-tax.

So income-tax is more liberal here than in other countries because we have completely left out one sector, the agriculture sector. I would request the Prime Minister to see whether it would not be more feasible to introduce agricultural income-tax. I believe it is a State subject. In any case, the States can be forced to go in for it, and, in fact, some States have gone in for it. Therefore, I submit that even on the income-tax side, the taxation is not very heavy, and is, in fact, on the liberal side.

Another theory is that the wealth tax is also very heavy. The wealth tax is imposed after granting an exemption limit of Rs. 1 lakh, and on the next slab it is hardly Rs. 400, a year, which is not very heavy. After a particular limit, it goes up to 10 per cent, but by no stretch of imagination can it be deemed to be very heavy taxation.

In fact, the taxation in India is not to an extent which will reduce wealth to a considerable extent. In spite of such alleged heavy taxation for the last 20 years, not a single industrial house has got lesser assets, in fact their assets have gone up. This really shows that ours is not a very heavily taxed country.

Another attack on the Budget is that it still supports the public sector undertakings. Public sector undertakings have given the greatest benefit to this country. No industrial house could have invested such a huge amount of Rs. 800 crores in industry. Not only this. They provide support to the ancillary industries. Further, they pro

[Shri Vikram Chand Mahajan]

vide employment. Of course, it is true that some are running at a loss, but there are industries in the private sector also which are running at a loss. In certain industries it takes a very long time for yielding large profits. The criticism of the public sector undertakings only on the ground of profits is totally meaningless because the object is not to make profits, but to create a public sector industry in the country which can provide a take-off for the future industrial development of the nation.

The wealth tax is reasonable and it cannot be heavier, because the maximum limit goes up to ten per cent, and the normal rate of return is ten per cent on any investment. Therefore, we are, in fact, taking away, by imposing a wealth tax of ten per cent, the entire income which accrues. More than this would mean that we are trying to take away the property as such.

The non-gazetted officers of Himachal Pradesh were promised Punjab scales when they came to Himachal Pradesh after the reorganisation of Punjab. They did not opt for Himachal Pradesh, but under the Act they were forced to go. Therefore, they should not be penalised for being forced to go to Himachal Pradesh. They should be given sufficient compensatory allowance and Punjab scales.

There are a few economies which can be effected without difficulty. The Prime Minister has been gracious enough to raise the exemption limit for income-tax to Rs. 5,000. This has resulted in the reduction of five lakh cases in the Income-tax Department. At the same time, wealth tax has been imposed on the agricultural sector which will result in creating about a lakh of cases. The net result is that there will be a reduction of about four lakh cases, and hence there should be a reduction in the Income-tax Department staff as such, but I find from the newspapers that due to the imposition of wealth tax, more than a hundred income-tax officers are to be appointed. I request the Prime Minister to look into this.

Secondly, there can be economy effected in the political structure of the country itself, and that money can be used for the development of the nation, for providing more basic industries which can create more employment. One of this is the new trend of development in our country: the abolition of upper Houses like Punjab, West Bengal. etc. They have saved millions for those States. The time has now come to reconsider whether the second House is necessary in Parliament also. The second House in Parliament has not contributed anything to Parliament as such. It was a theory propounded by some vested elements that the upper House gave maturer consideration than the lower Houses. The experience of the past twenty years has shown that the lower Houses are more mature than the upper Houses and in fact they act in a more responsible fashion whereas the Members of the Rajya Sabha are not so responsible.

MR. DEPUTY SPEAKER: No reference to the other House.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN: The upper Houses are not responsible either to the people or to anyone else.

SHRI S. KANDAPPAN : The position of the Rajya Sabha is different from the Upper Houses in the States; in our Constitution it is called the Council of States.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Their abolition would save money and from the point of view of our economy I feel that the money so saved could be used for the development of the nation.

The penalties which are provided under the Income-tax Act are very heavy and have not served their purpose; penalties are so heavy that the entire income is taken away plus a little more. The result is that the assessees who were willing to compromise before these penalties were introduced are not willing to compromise now and in fact the earnings by way of penalties had gone down instead of going up. For instance, penalty for late filing of returns was nominal previously and it could be collected. But now it is not so. A little money is given to the lower hierarchy of the income-tax department and the matter is squared up. This needs to be reconsidered.

In conclusion I submit that the present budget could not be better. Considering the situation prevailing at present this is the best budget and we support it.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : The Finance Bill and the budget proposals reflect the economic policy of the Government and determine to a large extent the economic activity and the financial stability not only of the Central Government but also of the State Governments. In a federal structure with an inbuilt bias in favour of the Centre it is bound to be so. In recent months, in the Indian economic landscape the Centre-State relations, particularly financial relations, have dominated the discussion. Apart from being an academic discussion, it is a very urgent problem, carying for immediate relief and solution. We should make a review of some of the important provisions of the Constitution regarding financial relations between the State and the Centre and see whether they had been observed in letter and spirit; it is a timely review. Article 274 of the Constitution particularly wants the prior recommendation of the President for bringing in a Bill affecting taxation in which States are interested. On how many occasions has the Centre approached or consulted the States before taking a decision on measures affecting States? For instance, the tax on railway passenger fares which was levied in 1957 weas repealed in 1961 without consulting the States. Also, a surcharge on income-tax was levied without consulting the States. An increase in excise duty by Centre on petrol restricts the scope of the levy of sales-tax by the States. In all these cases, we require that the Centre should consult the States before they take action. The Fourth Finance Commission has noted:

> "An explicit provision for a recommendation by the President should normally entail some mechanism other than the usual briefing and advice from the concerned Ministry at the Centre."

It is no use saying that we are consulting the concered Ministry and then proceeding. A mechanism should be devised.

In this connection, I may draw the attention of the House to a private Member's resolution tabled by me, but which unfortunately could not be reached on that day. In that resolution, I have demanded:

> "This House is of opinion that the Government should take immediate steps for formation of a permanent institution to make searching review of the Centre-State relationship in all aspects and to evolve and ensue functioning of full federalism, in spirit and in form, with greater devolution of power and maximum antonomy possible to the States in India."

Whether this can be done within the four corners of the present Constitution or we require any constitutional amendment should be considered, and it is time that we went into this matter. Unless the financial relationship between the Centre and the States is put immediately on a satisfactory basis, in the present context of different political parties putting strains and stresses on the Indian Constitution, it may become very late in the day to arrive at a solution.

The Administrative Reforms Commission has also gone into this question in a very exhaustive way and they have said in their report that the present state of affairs in the States' economy rests on the following three points: first, the resources for raising funds available to the States are comparatively inelastic. Two, the functions allocated to the States are such as lead compulsively to expanding responsibilities, particularly in the context of ambitious development plans; three, important resources for national plan financing are foreign aid and deficit financing, both tending to strengthen Central rather than State resources. Because of these three bases, the States have not been till date given a fair deal.

I want to concentrate on only one aspect of the States' instability of the financial resources. For example, the most disturbing feature of the State finances is the increasing burden of indebtedness. It is a very alarming position. Speakers in the Centre-State relations conferences have always drawn the attention of the Government, to the authorities that be, to the growing burden of debts on the States. The debt burden of the States in 1951-52 was only of the order of Rs. 445 crores. It has gone in 1968-69 to the tune of Rs. 7,032 crores. The debts of the States to the Centre—which is a more crucial one—stood in August, 1947, when

[Shri Sezhiyan]

India attained Independence, at only Rs. 44 crores. The entire States put together owed to the Centre only Rs. 44 crores at that time. Now, in March, 1970, it has gone to the tune of Rs. 5,997 crores: from Rs. 44 crores to nearly Rs. 6,000 crores, is a long track.

Then, about debt services; debt services by the States is a big burden put on their, slender resources. In 1951-52, all the States put together, had allotted only Rs. 8·49 crores for debt services. Now, in 1969-70, it has gone up to Rs. 640 crores, along with Rs. 264 crores of rupees as interest. The interest alone comes to Rs. 264 crores apart from the instalment payment. What happens is, unmindful of paying these things, the States go on taking loans. Whether they have got any idea of repaying in a future date, I do not know. (*Interruption*) Whatever loan is being given by the Centre to the States, a major portion of it is taken back by the Centre itself. In 1950-51, for Tamil Nādu Government, the amount repaid was less than 4 per cent of the financial loan assistance received from the Centre. But during the fourth plan the Tamil Nadu Government has been offered Rs. 140 crores of loan assistance from the Centre. But the Tamil Nadu Government is going to repay during the fourth plan about Rs. 160 crores. So, instead of the Centre assisting the States, the reverse is the process, the States are assisting the Centre. So, it is high time a Federal Debt Commission is appointed to go into the entire question. If you do not want to encourage reckless spending, if you want to infuse some responsibility to the States, it is high time you analyse the debts taken by the States and offer them a solution as to how best those loans could be avoided or liquidated.

In this connection, I have some suggestions to offer. Firstly, loans that have been taken for financing schemes that do not bring in a direct financial return to the State such as for education, medical facilities and rural manpower programmes should be treated as grants. Secondly, repayment of loans given as relief to goldsmiths or to repatriates from Burma and Ceylon or for relief of distress caused by natural calamities should be insisted upon only to the extent the State Government is able to recover it. The States did not want the Gold Control Act. *Suo motu* the Centre brought it. When thousands of goldsmiths were thrown out of employment, they were offered loans by the Centre, but all the loans were written in the name of the States and whether the loans have been recovered or not, the States are being asked to pay back the restalments of those loans. Therefore, when the State Governments have not had any share in taking the decisoin here to bring forward the Gold Control Act, the Centre should hold itself responsible for recovering the loans. We did not ask for the Gold Control Act. The Centre wanted it and they should face the consequences also. Why should they burden the States with the repayment of these loans?

Thirdly, repayment of loans taken for irrigation and power should be over a longer period. At present these schemes are financed through Miscellaneous Development Loans, which are repayable in 7 annual instalments with a grace period of three years. Irrigation and power schemes have a longer gestation period and returns will come only slowly. Therefore, repayment of loans taken for such schemes should be spread over 20 to 25 years. Whenever the Centre takes loan from the World Bank, it is spread over 40 to 50 years. They are soft loans with low rates of interest. But when the loans are given to the States, the repayment period is restricted to 7 years and the interest rates are high. As I said, important sources for national planning are foreign aid and deficit financing. For foreign aid, the period is longer and the interest rates is very low. For deficit financing, the interest is zero and the repayment period is infinite. When both these things are combined, to ask the States to repay it within 7 years and to charge a high rate of interest is not unjust and cruel, but it is going to upset the entire federation structure as far as financial relations are concerned.

Fourthly, adequate provision should be made in the States Revenue Account for amortisation of at least open marked loans and loans from Government of India at the end of a fixed period. These provisions are

not being made these days. Then at the end of the period, the States are put to a lot of hardship. The element of grant in Central Assistance for State Plan should also be considered and should be stepped up States will continue to be burdened with heavy debts.

Now, I want to discuss about the wrong, if not mischievous propaganda that is being carried out that the State of Tamilnadu is receiving special attention from the Centre, that is, from the Indira Government. They say because we are in the good books of the Prime Minister that is why we get much grant. I do not know what kind of book is being kept by the Prime Minister ; but the book-keeping of the Tamil Nadu Government does not show any encouraging results. Actually, we have not been given a fair deal. At every stage the due shares of Madras State have been slashed down. When the draft Plan was considered in 1966 they fixed the Tamil Nadu Plan at Rs. 564 crores. At the time we said it is not enough and wanted a higher rating to be given. The present Government considered very sympathetically and fixed it at Rs. 502 crores! I appeal to them that at least a minimum plan 574 crores is required. As regards Central Assistance in 1966 we were allocated Rs. 250 crores but the Central Government and the Prime Minister considered sympathetically and said it will Rs. 202 crores. In other things also, for example, take devolution percentages by the Finance Commission. There also percentages of sharing in regard to income-tax, additional customs duty have done down as far as the State of Tamilnadu is concerned. Therefore, Tamil Nadu Government has suffered at all points and at all stages.

The Central Government has appointed a pay commission to go into the salaries and allowances structure of the Central Government employees. The State of Tamilnadu has also appointed a Commission but the Finance Commission when it came refused to take into account the consequences of the Pay Commission appointed by Madras Government as on the day of the sitting up of the Finance Commission the Tamilnadu Pay Commission had not finalised their award. I would like to state here that scales of pay for the Tamil Nadu Government employees are much lower than that available in Kerala or Mysore. So, the Centre, they should take into account the pay-rise that will be demanded by State employees because *suo motu* if you do something, the State employees will clamour for parity Unless we make a re-appraisal of the constitutional provisions relating to the finances of both the States and the Centre, we will not be able to put the financial stability and make them really State on and truly partners with the Centre in building up the nation truly healthy

श्री राज देव सिंह (जौनपुर) : बजट प्रोपोजल्ज और वित्त विधेयक हमारे सामने है। इसके पहले भी हर साल यह लोक सभा बजट पास करती रही है। उन बजट प्रोपोजल्ज में और जो वर्तमान बजट प्रोपोजल्ज हैं, बहुत फर्क है। इसमें पहली बार कोशिश की गई है कि इस देश की गरीबी को मिटाने की दिशा में जितना काम किया जा सके, किया जाए। इसके लिए हम एक वित्त मंत्रालय को और खास तौर पर वित्त मंत्री जी को धन्यबाद देते हैं। जब इस सदन में बजट पेश किया गया था तब कोई अखबार या कोई ओपिनियन ऐसी नहीं थी जो उस से सैटिसफाइज न हुई हो। इसी से जाहिर हो जाता है कि हर वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया था।

देश म जो गरीबी व्याप्त है, उसको देखते हुए कुछ बातों की तरफ मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी आपने कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी घटा कर राहत दी है लेकिन दो आइटम्ज ऐसी हैं जिन पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे कामनमैन हिट होता है। एक सफेद कैरोसीन आयल है। लाल पर नहीं। लेकिन सफेद कैरीसोन आयल पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। गांवों में, देहातों में लोग इस तेल को लालटेनों में जलाते हैं। यह तेल अच्छी रोशनी देता है। मैं मानता हूं कि जो अमीर लोग हैं गांवों में या कसबों में या शहरों में वे भी इस तेल को जलाते हैं। लेकिन उनके यहां बिजली भी है, पैट्रोमैक्स भी है। लेकिन सब से ज्यादा सफेद

[श्री राज देव सिंह]

कैरोसीन आयल पर इस ड्यूटी का जिन पर असर पड़ा है, वह गरीब तबका है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि जो एक्साइज टैक्स इस पर बढ़ाया गया है, इसको हटा लिया जाए।

दूसरी आइटम पैट्रोल है। पैट्रोल केवल बड़े आदमी इस्तेमाल करते हैं ऐसी बात नहीं है। टैक्सी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले और वे जो किराये पर चलते हैं, भाड़े पर चलते हैं, वे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इन वाहनों को कामनमैन भी इस्तेमाल करता है। इस टैक्स के बढ़ जाने से उनका किराया भी बढ़ जाता है। यह कामनमैन की पाकेट को एफैक्ट करेगा। इस वास्ते इस पर भी आप पुनः विचार करें तो अच्छा होगा।

22 साल के बाद आज भी हम अपने देश में छोटे-छोटे कसबे, मध्यम साइज के शहर और बड़े शहर और साढ़े पांच लाख गांव देखते हैं। स्वराज्य के पहले जब हम गांवों में आते थे उस समय हमें ऐसे लोग देखने को मिलते थे जिनकी पूरी जिन्दगी बीत जाती थी लेकिन उनको पैर में जूता पहनना मयस्सर नहीं होता था, पूरी उनकी उम्र बीत जाती थी जाड़े के मौसम में उनके बदन पर ऊनी कपड़ा नहीं होता था। आज 22 साल के बाद भी हम देखते हैं कि साढ़े पांच लाख गांवों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया गया। लेकिन इस बजट में प्रोपोजल है उन गांवों की तरफ ध्यान देने की जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत से कारखाने खोले हैं, बहुत सी चीजें जो हम विदेशों से मंगाते थे अब हमारे देश में बनने लग गई हैं और हमारे देश की नैशनल वैल्थ और नैशनल इनकम बढ़ी है। लेकिन जो नैशनल वैल्थ या नैशनल इनकम बढ़ी है उसका प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। नतीजा क्या निकला है, इसको आप देखें। आज हमारी सोसाइटी में टाप पर पांच परसेंट लोग हैं और ये पांच परसेंट तीस परसेंट नैशनल इनकम और नैशनल वैल्थ को दबाए बैठे हैं। अगर नैशनल वैल्थ और नैशनल इनकम का प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता तो यह हालत न होती। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे देश की आज आबादी 52 करोड़ के करीब है। आप यकीन मानिये कि इस आबादी में से पांच करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। बीस करोड़ ऐसे हैं जो किसी तरह एक समय खा लेते हैं। और बीस करोड़ ऐसे हैं जो पेट भर लेते हैं दोनों समय। उनका खाना अनबैलैन्स्ड होता है, वह हैल्दी खाना नहीं होता है। पांच परसेंट ही हैं जो सचमुच खाना खाते हैं। अढ़ाई परसेंट वे हैं जो जो चाहते हैं वह खा लेते हैं। यह तस्वीर है हमारे देश की। आज तक जो हमने किया है वह बहुत नाकाफी है। तीन हजार करोड़ रुपया हमने इरिगेशन पर खर्च किया है। लेकिन आज भी 22 परसेंट से अधिक जमीन उस जमीन में से जो कल्टीवेबल है, हम इरिगेट नहीं कर सके हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मैंने वित्त मंत्री जी से दो चीजों पर एक्साइज टैक्स घटाने का अनुरोध किया है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि पैसा भी तो आना चाहिये। मैं बताऊंगा कि किन मदों से आपको पैसा मिल सकता है। हमारे साथी जो हम से पहले बोले हैं और हमारे दल के हैं उन्होंने एक सुझाव रखा है कि जो सैकिंड चैम्बर हैं लैजिस्लेचर्ज में, स्टेट्स में,—यहां की बात नहीं करता हूं—उनको एबालिश कर दिया जाए। देश के लोगों का थिंकिंग इसी ढंग से चल रहा है। उससे बहुत-सा पैसा बच जाएगा। सैकिंड चैम्बर्ज का एक महत्व था, एक इम्पार्टेंस थी, एक इस्तेमाल था। लेकिन अब अपर चैम्बर लोअर हाउस के इंडैक्स हो गए हैं। हारे हुए पालिटिशियन्स को बैक डोर से उनमें जगहें मिलने लग गई हैं। जो मकसद था सैकिंड चैम्बर्ज का वह समाप्त हो गया है। इसलिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

इस वास्ते मेरा अनुरोध है कि जिन स्टेट्स में सैकिंड चैम्बर हैं, वहां इनको समाप्त कर दिया जाए।

गांवों की समस्या आज जटिल है। गांवों की हमने उपेक्षा की है। उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिये थी। कारण यह है कि गांवों की जो कृषि है उसका राष्ट्रीय आय में स्तर परसेंट का योगदान है। हम गांवों की तरफ विशेष ध्यान दे कर इसको अस्सी परसेंट बढ़ायें या इससे भी आगे बढ़ायें।

पचास लाख लोग हर साल गांव छोड़ कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। बड़े-बड़े शहर जहां उद्योग धंधे हैं, उनकी आबादी हर साल बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि गांवों में उन्हें कोई पेशा नहीं मिलता। गांवों में उन्हें काम दे कर शहरों की तरफ भागने से रोका जा सकता है। इस ओर आप ध्यान दें।

गांवों में लोगों के पास रहने के लिए मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। उनकी जो सराउंडिंग्ज हैं, वे बीमारी लाती हैं। न्यूट्रिशस खाना उनको नहीं मिलता है। कर्ज के बोझ से वे लदे हुए हैं। यह 95 परसेंट गांवों में रहने वाले लोगों की हालत है। कुछ पार्टीज हैं जो अगर गांवों से टैक्स वसूल किये जाते हैं तो उसका विरोध करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास पैसा है, जो वहां टैक्स देने लायक हैं, उनसे जरूर लेना चाहिये लेकिन कोशिश यह की जानी चाहिये कि जो देने लायक नहीं हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े।

अनएकाउंटिड मनी हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि सरकार भी उससे परेशान है। है। इसको निकालने का भी आपको तरीका ढूंढना होगा। किस तरह से इसको खर्च किया जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बनारस में एक तुलसीदास मानस मंदिर बना है। सुरेका नाम का कोई कैपिटलिस्ट है जिसने अनएकाउंटेड मनी में से अठारह लाख रुपया खर्च करके इस मंदिर को बनवा दिया है। जो एनफोर्समट सैक्शन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वह इन चीजों की रोकथाम नहीं करता है। देखा जाना चाहिये कि अनएकाउंटेड मनी बाहर आए और वह अच्छे कामों में लगे, प्रोडक्टिव परपजेज़ म इस्तेमाल हो।

बजट में 115 करोड़ रुपया स्माल फार्म्ज़ और एग्रिकलचर लेबर की तरक्की के लिए रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि इसको बढ़ा कर दो सौ करोड़ कर दिया जाए।

67.5 करोड़ रुपया स्माल फार्म्ज़ की हालत को अच्छा बनाने के लिए रखा गया है। इसके लिए आपने कहा है कि आप 45 सैन्टर चुनेंगे। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्ज हैं, आंकड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो सब से गरीब 58 जिले हैं, कम से कम उन 58 जिलों के गांवों को तो इसमें शामिल किया जाए।

गांवों के लोगों के लिए एम्पलायमेंट आपरचूनिटीज उपलब्ध करना बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्रीज का डिसपर्सल करना चाहिए। इसके साथ ही गवर्नमेंट को स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए। उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई जिला उनसे खाली न रहे। गांवों के पढ़े-लिखे नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनके लेबर को-आपरेटिव्ज और इंडस्ट्रियल को-आपरेटिज बनाये जायें और नैशनलाइज्ड बैंकों से उन्हें लोन दिये जायें। इस प्रकार उनको काम मिलेगा और देश की दौलत बढ़ेगी।

न्यूट्रीशन प्रोग्राम के सम्बन्ध में जो पहला कदम उठाया गया है, वह बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें गोल-माल बहुत होता है। छोटे बच्चों और प्रैगनेंट मदर्ज की परवरिश के लिए हमें कई देशों से मिल्क पाउडर मिला है। हमारे जिले में, और कई दूसरे जिलों में भी, प्राइमरी स्कूलों के टीचर उस मिल्क पाउडर को ब्लैक में बेचते हुए पकड़े गये हैं। चाहे टीचर हो और चाहे हैड-मास्टर जो कोई बच्चों की खुराक

[श्री राज देव सिंह]

को बाज़ार में बेचने का हिनियस क्राइम करता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश एक तरह से हमारे देश का बीमार राज्य है। बड़े-बड़े नेता वहां के चीफ़ मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 1947 में था, उससे आगे नहीं जा सका है। 1951 में जब कि हिन्दुस्तान की नैशनल पर कैपिटा आमदनी 247.50 रुपये थी, यू० पी० की पर कैपिटा आमदनी 259.62 रुपये थी, लेकिन तीन फ़ाइव-यीअर प्लान्ज़ और तीन सालाना प्लान्ज़ चलने के बाद जब पूरे देश की नैशनल पर कैपिटा आमदनी 315 रुपये हो गई, तब यू० पी० की पर कैपिटा आमदनी घट कर 254 रुपये हो गई।

एक माननीय सदस्य : वहां की जनसंख्या बढ़ गई है।

श्री राजदेव सिंह : जनसंख्या तो हर प्रदेश की बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा आमदनी इतनी कम बढ़ी कि बढ़ी हुई जनसंख्या ने उसमें पहले से भी कमी कर दी—259.62 रुपये से 254 रुपये कर दी। एक तरह से हम पीछे गये हैं।

डी० एम० के० के एक माननीय सदस्य ने कहा कि मद्रास के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। मैं भी कहता हूं कि नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि एल० आई० सी० ने हाउसिंग के लिए 14 करोड़ रुपया हाउसिंग मिनिस्ट्री को दिया, जिसमें से यू० पी० को 100 लाख रुपया मिला और मद्रास को 150 लाख रुपया मिला, जब कि आबादी के हिसाब से यू० पी० को 300 लाख रुपया मिलना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि मद्रास को ज्यादा मिला है। हम यह कहते हैं कि हमें कम मिला है; आबादी के अनुपात से हम को मद्रास से दुगना मिलना चाहिए, लेकिन हमें उससे कम मिला है। हम महसूस करते हैं कि यू० पी० को दबाया जाता है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां की हैं, इस लिए वह इस बारे में कुछ बोलती नहीं हैं। यू० पी० का ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी पिछड़ चुका है। अगर यू० पी० पिछड़ा रहेगा, तो देश नहीं उठ सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने रूरल पावर स्कीम को बन्द कर दिया है। मालूम नहीं, केन्द्र में उसके लिए क्या प्राविज़न है। उस स्कीम से गांवों के लोगों को छोटी-छोटी मज़दूरी मिल जाती थी और समाज को सड़कें और पुल मिल जाते थे। उससे दोहरा फ़ायदा होता था। मैं प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि वह दबाव डाल कर उत्तर प्रदेश सरकार से इस स्कीम को चालू करायें और उसके लिए काफ़ी रुपया-पैसा दें।

इंडस्ट्रीज़ के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। चेकोस्लोवाकिया के कोलैबोरेशन से एक ट्रैक्टर फ़ैक्टरी रामनगर में लगने वाली थी। लेकिन वह पिंजोर में लग गई। वह तो ठीक है, लेकिन दूसरी ट्रैक्टर फ़ैक्टरी उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। वह एक एग्रीकल्चरल एरिया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर का ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके बारे में पटेल कमीशन ने सिफ़ारिश की थी। हमारी यह डिमांड है कि जो स्कूटर फ़ैक्टरी पब्लिक सैक्टर में लगने जा रही है, उसको जौनपुर में लगाया जाये। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेंगी, तो ऐसा हो सकता है। मेरा आग्रह है कि वह इस बारे में सोचें।

एक वैगन बिल्डिंग फ़ैक्टरी को यू० पी० में लगाने की बात थी। मालूम नहीं, उसको क्यों मुल्तवी कर दिया गया है।

एटामिक पावर स्टेशन के लिए यू० पी० गवर्नमेंट नरूला, अलीगढ़, में सब इन्तज़ाम कर चुकी है। वहां पर फ़ैंसिंग का काम हो चुका है। इसके अतिरिक्त वहां पर सब प्रकार की सहूलियतें भी उपलब्ध हैं। नार्थ इंडिया के

लिए वह सब से अच्छी जगह है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसका प्राविजन करे।

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampore) : Sir, I do not want to go into the details of the provisions of the Finance Bill which are well known. It would suffice if I say to-day that the measures proposed have not been of such a nature as to enthuse those who are of my persuation of thought.

I would rather prefer to utilise this opportunity in highlighting the economic and financial problems of the State of West Bengal. It is not very often realised in this House that the problem with which West Bengal is confronted to-day is not so much a law and order problem or a political problem but primarily it is a financial and economic problem.

The United Front Government broke up just on the eve of passing the budget. But the state of finances in West Bengal were as such that even if the budget were passed by the legislature, the state of economy would have been in doldrums. That is why, as one coming from that State, I have to come here and plead before the hole House, not only before the Government, not only before the Minister of Finance and the Prime Minister, but before the whole House to plead the case of West Bengal. The other day when the Bill for the delegation of Legislature powers of Parliament for West Bengal, to the President, was being discussed, I uttered a word of caution and said that Bengal was just on the brink of a revolutionary explosion. The real meaning of the violent manifestations of political disturbances and disruption have become almost the order of the day in West Bengal, and in the city of Calcutta and its suburbs and will not be understood unless we relate them with the state of economy there. But, before I do that, I would like to appeal to all sections of the House not to take my pleadings for West Bengal as coming from a regional spirit or narrow spirit. The previous speaker who spoke just now pleaded the case of Uttar Pradesh. As a matter of fact we are a very poor country and our politics to-day and for many years to come would remain a politics of scarcity and naturally representatives of every State assistance for their States. That is why I want particularly to impress upon the House that West Bengal is not only a State problem or a regional problem, it is primirily a national problem. It is not very often realised, Sir, what stakes people of other States have in the State of West Bengal. I have collected some figures from the Hazari Committee Report to which I would like to just make a casual mention. Before I come to Hazari Committee's report, I would refer to another significant figure. West Bengal provides jobs to above 60 lakh workers and other employed persons from different States. From the census taken in 1961 it was found that Rs. 28 crores were remitted from Calcutta every year in small postal money orders. That is the savings of small men without bank account. This was remitted to almost every State in India, but mostly in Bihar Eastern UP, Eastern MP, Orissa, Andhra, Tamilnadu and Kerala. Where would these people go if the economy of West Bengal collapses?

Coming to the figure given in Prof. Hazari's final Report on Industrial Planning and Licensing Policy, I find there very interesting figures Prof. Hazari has shown that out of total approved investments of Rs. 275 crores between 1959 and 1966, only 14 crores or a little over five per cent represented investments by Bengali entrepreneurs while Rs. 32 crores or 48 per cent were by Marwari entrepreneurs, Rs. 55 crores or 20 per cent were by Gujaratis, Parsees, Punjabis and other Indians. Rs. 8 crores or nearly 3 per cent from domiciled foreigners and Rs. 66 crores or 28 per cent from international combines. These figures represent only approved investments for a period of 7 or 8 years only and from that we can get an indication what total investment stakes people of other States have in West Bengal. If the economy of West Bengal today is in shambles let it not be thought that only Bengalis will suffer. As a matter of fact, the economy of the whole of the eastern region of India would suffer and that is why it is necessary to highlight this aspect of the problem. Somehow or other this problem, although it has been debated over decades, has not been solved and tackled. I do not have much time at my disposal and I would just mention what the mean aspects of the problem of West Bengal are.

[Shri Tridib Kumar Chaudhuri]

Firstly, the rate of population growth here is 32·8 per cent, second only to Assam, compared to the all-India figure of 21·5 per cent. You may add to that the problem created by the refugee influx from East Pakistan. Only yesterday the P.T.I. reported that during the last 3 months, 30,000 new refugees have come. And if our past experience is any guide, then all these people will ultimately become a burden on the economy of West Bengal.

Then, there is the chronic food problem and the problem of rice shortage. Rice is our staple food crop. But this rice shortage has been created mainly by transferring land from food crops to jute. The twin effects of this transfer and the industrial recession has been that we are confronted with a tremendous problem of unemployment. I do not want to go into the details, because that would take time. But in the jute industry, in 1952, the total employment figure was 2,75,000. In 1966, even before the United Front Government came into power, it had come down to 2,30,000.

Then the Calcutta region and Bengal as a whole is particularly dependent on the engineering industry. But the recession in the engineering industry has created another problem, and today, we are confronted in the State of West Bengal, according to the calculation of the experts, with a backlog of employment of 1,500,000, which before the end of the Fourth Plan will reach the figure of 3,300,000. Unless we tackle these basis aspects of the problem, the present problems, the political problems and the problem of disruption or violence that we witness in West Bengal cannot be tackled, and that can only be done if the Finance Ministry and the Planning Commission take matters seriously.

I can do no better than to quote from the budget speech of Shri Ajoy Mukerjee. Unfortunately, the budget could not be passed. But Shri Ajoy Mukerjee points out in his budget speech:

> "Originally, it was thought that an investment of more than Rs. 600 crores was necessary for West Bengal during the Fourth Plan period."

It was after a great deal of higgle-haggle negotiations that it was brought down to Rs. 321 crores. Shri Ajoy Mukerjee concludes his speech by saying:

> "It is a matter of no small regret that for the time being, the available resources do not add up to more than Rs. 321·50 crores. It may be remembered that we had spent Rs. 304·74 crores on our Third Plan. Indeed, having regard to the steady rise in price level since the end of the Third Plan and our Fourth Plan, if limited to Rs. 321·50 crores, it will in physical terms be smaller than the Third Plan."

Then, there is the problem of Calcutta. Several years back, the World Bank dealt with this problem, and as a matter of fact, a team of experts had come. The World Bank is still prepared to give sizable loans for rehabilitating the city of Calcutta. Government have agreed to a plan of Rs. 80 crores, of which Rs. 40 crores should be contributed by the Centre, but up till now, no implementation machinery has been created for this. So unless the Centre comes forward with determination to tackle these problem resolutely, I am afraid things cannot be improved, whatever may be the political measures you may think of. Now the new administration in West Bengal, after the imposition of President's rule, if we go by press reports and the information given by the Home Minister today, have suggested some kind of legislation for preventive detention and other repressive measures. But I would tell Government with all the emphasis at my command that these repressive measures would not do. Unless they are followed up with large scale constructive measures, the entire economy of Bengal will collapse, and if it does, it will bring down the entire eastern region of India. Not only West Bengal, but part of UP, a larger part of Bihar, a larger part of the economy of Assam, Orissa and North-Eastern Andhra Pradesh have Calcutta and West Bengal as their hub. This is a very strategic region, a part of the South East Asian region, and we must not forget that if we allow things to deteriorate in that fashion in West Bengal and in eastern India, a border area and a strategic area, not very far from Vietnam and other South East Asian zones, which are ablaze to-day, it will have disastrous consequences. If we move in a manner which allows things to drift it

would inevitably prepare the ground for a violent mass upheaval and a revolutionary explosion which will immediately engulf the whole country.

SHRI M. SUDARSANAM (Narasaraopet) : At the outset, I would unhesitatingly say that this year's budget certainly reflects the urges and aspirations of the common man. This is really a production-oriented budget. It is a very bold and clever budget, though it is called a political budget in certain quarters.

This Bill spells out the philosophy that strengthens the corporate sector to some extent and at the same times removes glaring inequalities of wealth through increased taxation of incomes over Rs. 40,000 and by placing additional burdens through tax and additional wealth tax on urban lands and buildings. If anyone makes a detailed calculation, one will realise that the taxation works out to more than 100 per cent. In referring to this matter, I am not unaware that it might lead to disincentives in earnings for the betterment of the economy. An imaginative budget could have exempted corporate profits to the extent of about 30 per cent as in Sweden when they are ploughed back into the industry. This alone can really solve our industrial proble and the unemployment problem. This will certainly increase the job potential and gross national product. I believe Government will assess its implications and would take requisite steps to provide reliefs wherever possible.

The Bill has led to a healthy rise in the share market to some extent because of the tax reliefs on incomes up to Rs. 3,000 on shares and also bank deposits, and the extension of Wealth-tax exemption etc. to Industrial shares and securities. In fact, the rise has been caused by taking advantag of these facilities for reduction of tax liability.

These, I feel, are only one aspect of our aims and aspirations. We have a lot of homework to do before we can hope to move in the direction of our goals.

Firstly, one must do some hard thinking on further improving agricultural, industrial and mineral production. Unfortunately, the impact of the Green Revolution has not percolated to cash crops. The transfer of improved technology can reach desirable proportions only if it covers cotton, jute, oil seeds and other types of agricultural produce, including tobacco, so that their increased per acre yields will result in cost reduction, larger exportable surpluses and, in some cases, release of acreage for further food production. Increase in mineral production through appropriate incentives can result in greater employment. As for industrial production, I am afraid, we are making too much of the recent improvement. Let us put the achievement in a proper perspective. From 1960 to 1965, we were achieving an annual growth at a compound rate of 8 to 9 per cent. There was a slide-back due to recession in 1966 when the index went down. In 1967, it further went down over 1966, If it improved by 6·4% in 1968, it has to be remembered that it was still below the index reached earlier. Similarly the improvement of about 7% last year would put our index perhaps only slightly above 1965. Therefore, what transpires is that we have only recovered the lost ground in the industrial field as a whole. Now to improve production further, new investment has to be generated with an appropriate balance as between consumer goods and heavy industries. The present situation is such that shortages have begun to develop in the raw material supplies of a larger number of items. The Economic Survey itself drew attention to the shortages in Oil seeds, cotton, iron and steel, staple fibre, non-ferrous metals, etc. Let us realise the implications of these shortages. Costs have risen and the profitability in some of the industries would go down either because of the existence of controls or because of the incapacity of the consumer to buy the goods at higher prices. In either case, two consequences flow-profitability goes down and with that there will be lower corporate earnings and fall in corporation tax realisation. Besides, shortages will lead to disillusionment in the society. I, therefore, suggest that a crash programme must be initiated to see what can be done to overcome these shortages and to augment industrial production.

Secondly, the ingenuity of the framers of the Budget proposals must come into play to correct a situation which has arisen, *viz.*, disincentive in purchasing new equity issues *vis-a-vis* investment in existing shares.

[Shri M. Sudarsanam]

This has occurred because of the withdrawal of the scheme of tax credit certificates in respect of investments in new equity issues and also because of the long gestation period in realising dividends from new companies. Already, there is a decline in the consents for the issue of capital as per Economic Survey of our Government. The decisions announced by Government on the Dutt Committee Report have opened a new Pandora's box in view of a number of legal and other issues that will require to be tackled. Also, the growth of new enterprises may be effected because of various factors. Here I refer to only one problem, *viz.*, that of streamlining the procedures for re-licensing of 41 delicensed industries, which is required to be done within a period of three months from the issuance of the notification on 19th February. At the same time, the real advantage of raising the exemptions limit to Rs. 1 crore can only be secured if appropriate facilities of foreign exchange for raw materials are provided.

In my view, the real solution to tackling the price situation is not at all through artificial controls, but through freeing the economy and creating an environment in which production can really increase. We already have appropriate strategic controls. Special consideration is essential for initiation of further welfare measures, as spelt out in the Central Budget, the scope of deficit financing which has been placed at Rs. 225 crores and what is most important, the continuing tendency of some of the State Governments to rely on over-drafts, without being able to raise additional resources.

Very unfortunately the Budget is not Export-oriented, because export duties on various items still continue, especially on tobacco. Export of considerable portions would suffer; unless the export duty is immediately abolished, tobacco will not be in the history of export commodities.

I suggest that we should endeavour to increase employment and employment opportunities through growth and productive efforts and not through increase in administrative expenses. The schemes outlined in the pamphlet "Towards Growth with Social Justice" will go some way in tackling the problem marginally. Here again, I would like to caution that these schemes must be implemented with a new missionary zeal through an ably chosen band of official who are dedicated to the spirit underlying the schemes, so that the problem to which our Government has turned its attention are gradually but surely, solved.

Coming to my State of Andhra Pradesh, the people are still subjected to droughts, famines and also cyclones. The *per capita* income in Andhra Pradesh is the lowest and much below the national average. It is industrially very backward; practically in the absence of sizable public sector projects, the possibilities of attraction of ancillary industries is also considerably narrowed down. I am heartened at the announcement of the Prime Minister about the three Steel Plants—Vizakapatnam, Hospet and Salem. I suggest that the formation of separate units is most essential so that work can be taken up in a serious manner. This will solve to some extent the unemployment problem in the local population.

The need for one more Refinery on the East Coast, especially at Kakinada, is keenly felt. This must be established at once, thus giving room for opportunities for petro-chemical projects on the East Coast. Priority must be given for rural electrification.

I am happy that the Government has inaugurated the scheme for mining copper, zinc and lead at Agnigundala. Here, I would like to appeal to the Government to create dynamism to put the plant into commission. The officers must work with missionary zeal. This project will be a very good foreign exchange earner, producing considerable quantities of lead, zinc and copper, for the betterment of the economy of our country. A full-fledged and Independent organisation is to be formed at once, for exploitation of the deposite with Headquarters in the Mining area.

Establishment of ZINC Smelter Plant at Visakhapatnam in Fourth Plan is also urgent. Government of Andhra Pradesh, already offered adequate land and water facilities and cheap power. This has been already approved by Government of India. Immediate steps for installation should be taken to avoid increased costs and bitterness and frustration in the minds of the people. With these remarks I support the proposals

of the Prime Minister and Finance Minister.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : We are not at the last stage of the discussion of the financial proposals and we have to consider seriously whether the Lok Sabha which is the watch dog of public finances is doing justice to all the demands that are being voted here. Whether it is due to lack of time or due to lack of proper arrangements.... (*Interruptions.*)

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj) : —or due to Members taking excessive time.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: He is talking rot. What I wanted to say is that we could not discuss as many as 11 Ministries. It was all guillotined. Actually speaking, I made a count. I find that only 16 per cent of the demands were discussed by this House. So, necessarily, I want the Leader of the House—of course she is never present—

MR. DEPUTY-SPEAKER : She was present; only a little while ago, she went out.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : She is sometimes present : I amend my statement. So, I want the Leader of the House and also the Chair to consider seriously when we discuss the budget in all stages, whether we should not arrange our programme in such a manner as to enable us at least to discuss each and every Ministry. It is essential because on the Appropriation Bill also, this House does not discuss the Ministries which have been left out. If time was given for discussion, during the Appropriation Bill, of the Demands of those Ministries which were left out, that could be done. But that is not being done, and so unless we all apply our mind to this, I think the Lok Sabha will be failing in its duty because the Rajya Sabha has not got this right or power to discuss these matters.

About the Finance Bill, I do not want to go into the details. I spoke in greater detail while speaking on the general budget. The Prime Minister has announced some small concessions. This concession, I take it, is very marginal. The concessions in respect of tea and other things is of course welcome. But what I find is, the additional revenue of Rs. 170 crores that would accrue, after this concession was given will be reduced by only Rs. 1·8 crores. That is nothing. Actually speaking, this indirect taxation will hit the common man. There is no doubt about it. The attempt should be, as far as possible, to arrange this taxation in such a manner as would not hit the common man much. We were thinking that there is some rational thinking, and actually the taxation proposals would be formulated in that manner. What little is given to the common man, as they say, in the shape of other concessions by this indirect taxation and fresh taxation, is neutralised.

Let me take the question of sugar. The Prime Minister did not mention about this at all, or, she did not think it proper—I do not know—although, as you know, almost all those who have spoken on the budget proposals in this House including Members of the ruling party have all opposed this levy on sugar and have pleaded that it should be withdrawn.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : None has spoken during this debate.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : That is what I am saying. When the general budget was discussed, all mentioned about it, I have given an amendment about this in the Finance Bill. Now, let us see whether it actually hits the common man or not. If we take the figures since 1948, I think the price of sugar has increased four times. Take the present levy, and see how it will affect. 75 per cent of the total production of sugar is on a quota basis and the rest for the free market. The price of the free market sugar fluctuates according to demand and availability. Because the Government has fixed the basis of the quota so low individually and also because there is a large section of the population who do not come under the quota system, and are compelled to buy outside the quota system, the run on the free sugar is almost compulsive. The result is, not only does the price of free sugar increase but Government tax thereon would also increase in greater proportion.

I have also figures to show that the *per capita* availability of sugar has come down

[Shri Surendranath Dwivedy]

and the total production of sugar in terms of gur has remained almost static. The recovery percentage has come down from 10·1 per cent in 1964-65 to 9·9 per cent in 1967-68 and to 9·4 per cent in 1968-69. Hence, whatever be the percentage of control, the whole of the excise duty will be passed on to the consumer. The excise duty on sugar, the sales-tax, octroi duties and other levies on sugar were to the tune of 25 per cent of its value. By this increase in duty, the percentage will increase very sharply. If the Government think that this is a luxury item, I have nothing to say. But if they do not think so, I will still plead with them that they should accept my amendment and withdraw this levy.

We have all welcomed agricultural wealth tax. But Government is still showing hesitation. I do not understand the purpose of the new announcement that farm houses should be excluded from the purview of taxation. According to the present Act, up to the value of Rs. 1 lakh, it was already being exempted. Really speaking, these farm houses are residential houses and people stay there. If you exclude the farm houses, then practically nothing will be left for taxation. For whose benefit is it being done? Probably the Government has in mind big landlords in Punjab or other places. Probably there are some people who have amassed great wealth through agricultural income and they have influenced the Government to do it.

14·53 hrs.

[SHRI SHRI CHAND GOYAL *in the Chair*]

The plantations also would come under the purview of this Act. Actually I find that as in factories, even small plantation owners have to build houses, schools, hospitals, etc. These are statutory obligations. If such cases are exempted, I can understand. But I really fail to understand for whose benefit they want to exclude farm houses. I hope Government would give serious consideration to these two matters.

I have already given an amendment about raising the exemption limit for income-tax to Rs. 7500, as recommended by the Bhoothalingam Committee. Government have accepted many other recommendations, but I do not know what prevents them from accepting this recommendation. If they do not want to go up to Rs. 7,500 as a compromise they could have at least gone up to Rs. 6,000. But they have not done so. It appears that by going up to Rs. 6,000 they could have removed 17 lakhs assessees out of a total of 28 lakhs assessees from the list and the total loss of revenue would not have been more than Rs. 7 crores to 8 crores. At the same time, the income-tax officers would have more time to deal with bigger cases.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : In the ultimate analysis, there would be no loss of revenue.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : My hon. friend says that there would be no loss of revenue. At the same time, there would be some relief to the lower middle class people. Otherwise, this concession will have no meaning because of the rise in the cost of living. I do not think this proposal will give relief to anybody.

There has been much talk about the public sector industries, especially the steel plants. I have dealt with it in detail in my budget speech. But I would be failing in my duty if I do not refer to it here. We have no concrete proposals before us in this House as to how the management of the public sectos is going to be improved. What are the concrete measures that the Government of India propose to take to improve the situation, keeping in view the criticism of the public sector undertakings not only by those who oppose it but also by various Committees of Parliament as well.

I am told that recently there was a seminar organised by some non-official body in which the Prime Minister and other Ministers participated. I do not know whether any instructions were issued by the government or not, but I am told that the representatives of management and workers of the public sector industries came and participated in this conference. At whose expense did they come? Did government issue any instructions that they should participate in a non-official conference? I may warn you that you are creating a very bad precedent by surreptitiously managing these things in such a manner that you make a show that your own men of the ruling party are organising this and then issue instructions to the

management and workers to participate in it. I know it for a fact that the representatives of the workers have been paid first class fare and their accommodation had been arranged so that they could participate in this seminar. Yet, most of them said that they do not know what was the purpose. So far as the discussions and decisions of the conference are concerned, they have no bearing on their own problems in their plants.

During the discussion on the Demands for Grants of the Steel Ministry the Prime Minister announced the location of three steel plants in the south. We all welcome it. But it looks as if in this country there is only north and south and no east and west.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : (Chittoor) : North have steel plants; there is one in Orissa.

15 hrs.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Why do you bring Orissa into the picture? Madhya Pradesh is very much in the picture. Now, what is the basis on which the locations have been decided for these three new steel plants? If the basis is that we must disperse our industries in different States and as Mr. Naidu insits that at leasts each State must have one steel plant then I have no objection; the economy of the country may go to dogs but we must have a steel plant in every State. If Government's consideration is that, I will not quarrel with them. In this connection I want the Government to consider and let us know whether location of industry—either steel plants or any other public sector industry—should be considered on State basis or political considerations, or on economic basis taking into consideration the national economy as a whole. I have collected some statements made by our friends—a statement by a Minister in Tamil Nadu Government and a statement by Mr. Brahmanand Reddy. The Tamil Nadu Minister says because we were supporting the Government and Government could not afford to displease us, so we have got Salem steel plant.

SHRI S. KANDAPPAN : The Minister did not say that it is because of the support that we got it. He did say: "We fought for it and we got it."

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : They fought for the Salem plant and got it and, therefore, they are celebrating the victory for it. One must fight to get it whether there is economic viability or not. Now, what does this Government want—it wants there must be fight, burning of trains, burning of houses, disturbances, etc. There will be all these agitations in order to enable a State to get a steel plant.

Take Madhya Pradesh and Orissa. In 1964 the late Governor of Orissa, Mr. Khosla, who is a technician himself has submitted a proposal. There are two places which are quite close to Rourkela—Bonai and Nayagarh—where the deposits alone would be to the tune of 29,000 million tonnes and for future we could have an integrated steel plant the capacity of which can easily be increased to 10 million tonnes. These facilities are there. All these places which economically or othrwise would also have got first priority according to me but when we plan something we must have at least some consideration to the overall economy of the country. That was completely ignored. The only answer that the Steel Minister has given here is that the Orissa Government sent their proposals only on the 5th March. The Orissa Government might fail in its duty. It may be possible that the Orissa Government was not very much interested; but now they say that they are very much interested. But will you consider it only from the point of view whether a particular Government wants it or not or whether your national economy demands that you must select the place and on your own you should take the initiative to find out which is the proper place for the location of such industries?

The steel industry has already got a bad name. Bokaro is failing and you are injecting politics into it.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Bokaro has not failed.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: It has not yet started and it might never start. It may take four years more. Before production the cost has been calculated to be three times more than what we are having in Rourkela. It is all in the formative stage. Wo do not know in which year Bokaro is coming.

[Shri Surendranath Dwivedi]

I want to know from Government why these cases, which were already with the Government, before the Planning Commission and their own ministry, were not given consideration and while deciding the location of these steel plants why they were ignored.

I will conclude by saying that if the Government believes that the only policy which will work and to which they will listen is agitation, I can give the Prime Minister this assurance that in Orissa—and, I think, Madhya Pradesh will join us—all parties irrespective of any political differences and the people of Orissa will start an agitation to see that the steel plant is ultimately located in Orissa, not by withdrawing what has been given to others but in addition to that. We must have a steel plant.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: We support it.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Thank you. Why I say this is because it will contribute to the national economy.

श्री बी० बी० तारोडकर (नादेड़) : सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जनता के प्रति अपने फर्ज और जनता की ख्वाहिशों को अच्छी तरह समझ कर उन्होंने चाय और दूसरी चीजों में करों की छूट दी है। उन्होंने जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनका उत्पादन 2 लाख रु० तक का होता है उनको कर से मुक्त किया है। इसी तरह से मैं प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि जो इस सदन में ही नहीं बल्कि देश में कई सालों से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग हो रही थी उन्होंने उसको मान लिया। हम देखते हैं कि बैंकों से हमारे देश के गरीबों को, सारे देश के करीब 80 प्रतिशत लोगों को, जो देहातों में रहती हैं, अभी तक जो सुविधायें मिलनी चाहिये थीं, वह नहीं मिल रही थीं। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ऐग्रीकल्चर (काश्तकारी) में लगे लोगों को बड़े पैमाने पर लोन आदि की सुविधायें मिलने लगी हैं। इसके लिये भी मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं इसके लिये भी प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ा कर 4200 से 5000 रु० कर दिया।

लेकिन साथ साथ इस बारे में भी मैं अपनी राय रखना चाहता हूं कि जिस वक्त श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, उन्होंने रिटर्न देर से दाखिल करने के लिये कड़ी पेनैलिटी इम्पोज की तथा इनकम टैक्स का असेसमेंट थोड़ा बहुत भी इन्क्रीज्ड होता है तब उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हेवी पेनैलिटी इम्पोज करता है। नतीजा यह होता है कि बहुत से करदाता अंदरूनी तौर पर इनकम टैक्स आफीसर को मिलाने की कोशिश की जाती है और इनकम टैक्स की राशि की कमी की जाती है। इस वास्ते इसमें थोड़ा-सा एमेंडमेंट करने की आवश्यकता है।

अब मैं एग्रिकलचर वैल्थ टैक्स के बारे में एक सुझाव रखना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस टैक्स का स्वागत किया जाना चाहिये। आप देखें कि हमारे देश में जमीन का छोटे छोटे टुकड़ों में बटवारा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि लैंड सीलिंग की बजह से जमीन एक व्यक्ति के पास ज्यादा नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में लैंड सीलिंग आ चुका है। वहां तीस एकड़ की लिमिट लगाई गई है। हम नारा देते हैं कि एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन हमारा बढ़ना चाहिये। लेकिन आप देखें कि एग्रिकल्चरल वैल्थ टैक्स अगर इम्पोज किया गया तो उसका क्या असर पड़ेगा। आपने इनकम टैक्स की लिमिट को पांच हजार तक बढ़ा दिया है। जिसकी वजह से दो लाख केसिस इससे कम हो गए हैं। लेकिन यह जो एग्रिकलचरल वैल्थ टैक्स आप लगा रहे हैं इसकी वजह से पचास हजार से ले कर एक लाख केसिस बढ़ेंगे। इस कारण से काश्त करने वाले जो लोग हैं उन पर कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, क्या इसका भी अंदाजा आपने लगाया है? उनको

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी । अगर वे सही न हुई या उन्होंने इनको देर से दाखिल किया तो उन पर बड़ी पैनेलटीज इम्पोज होंगी । इसका सीधा असर अनाज की पैदावार पर पड़ेगा । अगर आप चाहते हैं कि पैदावार बढ़े तो वैल्थ टैक्स को आपको खतम करना चाहिये । अगर ऐसा आपने किया तो जनता आपको बधाई देगी और खास तौर पर जो काश्त करने वाले लोग हैं, वे आपको बधाई देंगे ।

रिजनल इम्बैलेंस के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं । हमारा मराठवाडा का इलाका है । हम पहले हैदराबाद स्टेट में रहते थे । यह देश का एक बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बैकवर्ड एरिया है । यहां कोई भी पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है । जिस वक्त यह एरिया महाराष्ट्र में विलीन हुआ था उस वक्त रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था । जितना भी इस एरिया का सरपलस एमाउंट है वह उसी एरिया में रेलवे के एक्सटैंशन (बढ़ौती) पर लगाया जाएगा । इस एग्रीमेंट को हुए बारह चौदह साल हो गए हैं । वहां एक मील का भी एक्सटैंशन नहीं हुआ है । कई करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया है । मराठवाड़ा के लोगों का ख्याल ऐसा है कि सैंटर का उनकी तरफ ध्यान नहीं है । वहां के लोगों ने मनमाड मुदखेड़ ब्राडगेज की मांग की थी । लेकिन ब्राड गेज भी नहीं दी गयी । आज हमारे देश में जगह जगह एजीटेशन चल रहे हैं । हर स्टेट में हम देख रहे हैं कि एजीटेशन चल रहे हैं । नई नई स्टेट्स बनाने की मांगें उठ रही हैं । पृथक तेलंगाना की मांग चल ही रही है । मराठवाडा के लोगों के मन में इस तरह की कोई फीलिंग न हों कि उनको इगनोर किया जा रहा है, इस तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है । पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्री आप वहां दे सकते हैं । लेकिन वह भी आपने नहीं दी है । किसी चीज में सेंटर से कोई मदद नहीं मिली है । मेरी प्रार्थना है कि सैंटर की ओर से हमारे इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उसके लिए कुछ किया जाना चाहिये, उनकी मदद की जानी चाहिये ।

मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि नांदेड, औरंगाबाद आदि मराठवाडा के एरिया में बहुत भारी फ्लड आया था जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन वहां बह गई थी । इससे वहां पर अनएम्प्लायमेंट की प्राबलैम पैदा हुई । इसको ले कर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डैलीगेशन वहां पर भेजा है जो सर्वे कर रहा है । जिस तरह से केन्द्रीय सरकार राजस्थान तथा दूसरी स्टेट्स की मदद कर रही है सूखे आदि की स्थिति का मुकाबला करने के लिए, उसी प्रकार से वहां भी मदद सैंटर की ओर से होनी चाहिये और कुछ बिल्डिंग्ज, रोड्स पीने की बावलिया, टेलीफोन के खंबे आदि काम निकाले जाने चाहियें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । इसके लिए स्पेशल फंड, आप निकालें और उनको काम दें । इससे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको कुछ सुविधा मिल सकेगी । मराठवाड़ा में सबसे कम काम टेलीफोन और पोस्ट का है—अभी तक तालुका और 10,000 की आबादी को फोन नहीं है जितने मैं भी एक या दो डाइरेक्टर लाइन्स है, जिससे बाहेर गांव के फोन 6 और 9 घंटे तक नहीं मिलते । पोस्ट आफिस के लिए बिल्डिंग नहीं है ।

अब मैं एग्रिकलचरिस्ट लोगों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । देहातों के कितने ही लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं । जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वे शहरों में आ कर बसने की कोशिश करते हैं । इस कारण से जो अनएम्प्लायमेंट प्राबलैम है वह बढ़ रहा है । मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ड्राई लैंड (बगैर पानी की जमीन) के बारे में बड़ी अच्छी योजना बजट में पेश की है । मैं चाहता हूं कि ड्राई लैंड वालों को और ज्यादा सुविधायें आप दें । साथ ही साथ जो गांव के विद्यार्थी पढ़ लिख जायें और जो शहरों में जा कर बसना

[श्री बें० बा० तारोड़कर]

चाहते हैं उनके लिए आप वहीं पर इंडस्ट्रीज की तथा दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था कर दें। वहां आप एग्रो इंडस्ट्रीज खोल कर इनको काम से लगा सकते हैं या इनको प्रोत्साहन दे कर इनके द्वारा इन इंडस्ट्रीज को चालू करा सकते हैं। इससे काफी तरक्की हो सकती है। जापान एक छोटा-सा देश है। वहां एग्रो-इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं और हम देखते हैं कि वहां बड़ी तरक्की हो रही है। हमारा देश एक विशाल देश है। फिर भी वहां सुविधाओं के अभाव में ये इंडस्ट्रीज नहीं खुल पा रही है और देश उस देश की तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा है। मैं आपको इसके साथ साथ इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस साल आपने 58 जिलों को सिलैक्ट किया है जहां पर आप खास तौर पर ध्यान देंगे और धन लगायेंगे।

महाराष्ट्र की दृष्टि से गोदावरी और कृष्णा का जो प्राबलैम है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्राबलैम है। प्रधान मंत्री जी को मालूम ही है कि इसकी वजह से महाराष्ट्र में बड़ी परेशानी है। आप यह भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त केवल छः परसेंट भूमि में इरिगेशन का प्रबन्ध है जबकि बाकी देश को देखा जाए तो वहां 26 परसेंट में इरिगेशन होती है। महाराष्ट्र की और देश की भी यह ख्वाहिश है कि हमारी पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ प्राजैक्ट्स हैं जिनको हम हाथ में लेना चाहते हैं। सैंटर के पास महाराष्ट्र के बहुत से प्राजैक्ट सैंक्शन के लिए पड़े हुए हैं। उनके सैंक्शन नहीं दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही गोदावरी और कृष्णा का जो सवाल है और जो कई साल से लटका हुआ है, उसका हल भी निकाला जाए। इसमें खास तौर पर आप दिलचस्पी लें और इसको साल्व करें। तथा कयादू मराठवाडा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये महाराष्ट्र सरकार की निधि से चल रहा है। उसे सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड करे तथा दूसरे प्रोजेक्ट जैसे ऊपर परगना, अपर वर्धा, अपर ताप्ती, पेंच, दूधना, लोंडी तीलारी, मांजरा को स्वीकृति जल्दी दें।

महाराष्ट्र ने ज्वार का मौनोपोली प्रोक्योरमेंट शुरू किया है, इसको अपने हाथ में लिया है। इसका वहां लोगों ने स्वागत किया है और इसके लिए वहां की सरकार धन्यवाद की पात्र है। महाराष्ट्र में कपास भी बहुत ज्यादा पैदावार होती है। कपास की कीमत भी ज्वार की तरह किसानों को ठीक नहीं मिलती है। महाराष्ट्र का इरादा है कि जिस तरह से ज्वार को अपने हाथ में लिया है उसी तरह से कपास की काश्त करने वालों को पूरी कीमत दिलाने के लिए, वह इसको भी अपने हाथ में ले ले। वह इसमें सैंटर से मदद चाहती है और मैं प्रार्थना करता हूं कि उसको यह मदद दी जाए।

अन्त में आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अगर प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने मराठवाडा की प्रावलैम्ज की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Sir, there is a wrong notion among politicians in all Parties that the agriculturists are making lot of money due to the green revolution. This is a very wrong notion. I am only sorry for them. These people who do not know A, B, C, D of agriculture have become our leaders. It is unfortunate. About 80% of our population depend on agriculture. Agriculturists and labour, both combined, constitute 85% of the population and the balance 15% who do not know A, B, C, D of agriculture have bossed over them and they do a lot of harm.

Last year when Morarji Bhai was the Finance Minister, he introduced this Agriculture Wealth Tax and Fertiliser tax. At that time some members said that it was Morarji Bhai who did it and the Prime Minister has got all sympathy for the agriculturists. Now Morarji Bhai is gone and the Prime Minister is the Finance Minister. She must show her sympathy by withdrawing this wealth tax. She has shown only a small mercy of exempting the farm houses. Who

is having such big farm houses? Not the poor farmers. I want the Prime Minister to tax the farm house and leave off the land. Let her tax this farm house and leave off these lands from the agricultural wealth tax. Only the rich people, the rich peasants who can afford to spend Rs. 2 lakhs or 3 lakhs could have farm houses. The poor agriculturists have not got these farm houses. So, please tax the people who have got big farm houses and exempt these lands from the tax. This is my request to you. Agricultural wealth tax by the Centre is itself a wrong thing. Some people say, agriculturists have made lot of money. Only within 2 or 3 years they are able to see some money but for all these years, for all these centuries together, they were downtrodden and they were not able to educate their children and they have suffered. It is only now that they see some money and now these people's eyes have become sore. May I know whether these agriculturists are having air-conditioners in their houses or air conditioned cars? They are only investing this money in levelling the land, deepening the well, purchasing the tractors, etc. They are using more fertilisers. When they are doing all these things, why should you tax them? This method of taxation, the agricultural wealth-tax, is itself a wrong thing. For the States, this is the only main income. The main income of the States is from land revenue. And, you want to encroach on that also. You want to encroach there and have that amount and you say you will distribute that amount. To whom ? To whom soever supports you and others won't get it. I tell you, in so many States the land revenue has been doubled and trebled. Why do you think that they have not taxed? They have already taxed. The State Governments have already tken steps and they have already taxed. And now, in addition to that, if the Central Government also wants to tax, is it fair? I am asking you. My only request to the Prime Minister is this: Don't take away this main income from the States. Wherever they have not taxed, ask the States to tax them, but wherever they are already taxed you can't impose another tax. This is my only humble suggestion. My only request is that the Prime Minister may consider this and in the end this tax may be withdrawn. Otherwise, Madam, what happened to Morarjibhai will happen to you. Please consider this.

Regarding sugarcane I want to bring this thing to the notice of the Prime Minister. The Prime Minister has got only 5 acres of land and she has grown some wheat only. She might know about wheat, but about sugarcane she does not know. That is why I want to tell her about this. Now the Government has fixed the price of sugarcane at Rs. 73 minimum price. Do you know the cost of firewood in the city, Madam? It costs Rs. 125. For growing firewood you have given more concession. You have got more sympathy to the people who grow firewood than to the people who grow sugarcane. Sugarcane needs more watering, more manure, more labour. But in respect of firewood, within two years, you get double the quantity and you can make Rs. 125.

You will please consider this. Since you do not know anything about agriculture, I am bringing this fact to you.

SHRI S. KANDAPPAN : He is addressing the Prime Minister. Let him address the Chair.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I am addressing her through you, Mr. Chairman.

Now take the cost of fertilisers. It is the highest here. Nowhere in the world the fertiliser costs so much as in India. Though the prices of other commodities have gone up, at least Government should see that the price of fertilisers is not high. Agriculturists are expected to use more manures. And there is a wrong notion that only the rich people use the fertilisers and the poor do not use them. I am sorry for it. Actually, the rich people do not care for this whether they grow or not. But, the poor people have to put in a little more efforts for growing more foodgrains. And if the poor agriculturists are taxed even on fertilisers how can you expect them to grow more? I only appeal to the Government to remove the fertiliser tax from the taxation proposal so that the poor people may use more and more fertilisers and grow more foodgrains so that you need not have to depend upon America.

The Prime Minister has said in her budget speech that she is going to give some relief or some help to the people in the dry-farming area. In the dry-farming areas, only the

[Shri Chengalraya Naidu]

rich people purchase lands. In Delta areas they purchase lands and they have better water facilities here whereas the poor people are having their lands in dry areas because they cannot afford to purchase lands in the delta areas.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I have got four or five minutes.

MR. CHAIRMAN : There are five speakers from your party. I do not mind your exhausting the entire time that will be required by the other members of your party. However you may take one more minute if you want.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I was telling that these people are growing groundnut oil seeds and other things in the dry land areas. What relief are you going to give to them? You have not even fixed the minimum price for the groundnuts and other things. When the agriculturists get the produce to the market the price is low. But, when the merchants get them, the price goes up. Why cannot the Government fix the minimum price? Every year, this Government is importing lakhs of tonnes of soyabean oil from America. We want to be self-sufficient in food-grains as also in soyabean edible oil. But, we are getting them from America and Russia. Is it not telling on our efficiency ?

So, I request the Prime Minister to fix up the minimum price for the oil-seeds. Only the oil-seeds are grown in dry land areas. If you have got really sympathy for these poor people, please fix up the minimum price for this that sufficient quantity of these oil seeds is grown and these are given to the oil manufacturers.

MR. CHAIRMAN : Now you must conclude.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I am concluding. I agree that the Prime Minister wishes to collect some tax for the development. For whose development does she collect the tax? Not for our development but for the development of Russians. Every Russian Engineer, for example, is paid Rs. 35,000 per month with air-conditioned rooms etc., etc. With this amount, you can feed seventy unemployed engineers in our country. What are you doing? Every useless item of machinery is bought from Russia and is assembled here. In Hyderabad, there is a synthetic drugs factory. The plant there is an old one. There is another synthetic drugs factory in Rishikesh. That is also an old one. All these plants were rejected by China, but they were painted and brought back to India and fitted here. If things are going on like this, I do not know what is going to happen.

I have to congratulate the Prime Minister on withdrawing the concession in regard to having guest-houses so far as the corporate bodies are concerned. That is very good. But what about the Prime Minister ? She has appointed communist card-holders as chairmen of the public sector projects, ahd they are having guest-houses. Why should the corporate sector be deprived of these guest-houses, while at the same time, the public sector projects are allowed to have them ? I cannot understand this. Why should there be this discrimination between private sector and public sector in the matter of guest-houses? Our communist friends have complained several times about the misuse of these guest-houses for political purposes in Kerala. Very recently, some Gujarat MLAs were brought here and accommodated in some guest-house in Delhi. This is how the guest-houses are misused by them. I appeal to the Prime Minister to see reason, and to see the agriculturists' plight. Let them not be taxed. There is only one tax left to the States, and that is the agricultural land revenue. Let the States not be deprived of this. I only appeal to the Prime Minister once again to see that the agricultural wealth tax is withdrawn. Otherwise, in 1972, the people will show what it would mean.

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : सभापति जी, मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री का ध्यान पहले तो इस बात की ओर दिलाऊंगा कि उन्होंने बार बार कहा है कि जो कुछ क्रिटिसिज्म होता है, आलोचनाएं होती हैं वह मोटिवेटेड मतलब से होता है। होती होंगी । मैं इनकार नहीं करता । किन्तु साथ ही साथ उसका दूसरा पहलू है कि जो तारीफें होती हैं

वह भी तो मोटिवेटेड होती होंगी । यह तो नहीं हो सकता कि तारीफें तो सोलह आने सही होती हों और क्रिटिसिज्म ही मोटिवेटेड होता हो । इसलिए जब तारीफें अच्छी लगती हैं तो कड़वी बातें भी सुनने की आदत डालनी चाहिए । नहीं तो जो राजा अपने मंत्रियों से सिर्फ मीठी मीठी बातें हीं सुनना चाहता है वह अपने राज को अधिक दिन टिका नहीं सकता ।

इस समय यहां देश पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, बाहर से भी और भीतर से भी । बाहर का खतरा यह है कि हर मौके पर जो असली चीज है उसे परदे में डाल कर दूसरी बात कही जाती है । बंगाल में और और सब जगह स्टूडेंट्स अनरेस्ट और ला ऐंड आर्डर की प्राबलम छात्रों में क्रोध, क्षोभ तथा सामान्य सुरक्षा की समस्या कही जाती है और ला ऐंड आर्डर की प्राबलम की जड़ में एकोनामिक डिस्ट्रेस गरीबी की बात कह दी जाती है । यह बात पौने सोलह आने सही है कि एकोनामिक डिस्ट्रेस है, बहुत दिनों से है । लोगों पर जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं । लेकिन इसमें कोई वही असल अकेली चीज नहीं है । यह बातें तो सैंकड़ों सालों से चली आ रही हैं । मगर आज इसको बहाना बना कर किया क्या जा रहा है । उस पर आप को सोचना है और सोचना चाहिए । आज तो इस मुल्क में यह बात हो रही है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उसे देखिए, हर जगह गांधी जी के नाम पर, हर जगह नेहरू के नाम पर, अब तो यहां तक कि सुभाषचन्द्र बोस और टैगोर के नाम पर भी कालिमा लगाई जाती है, गालियां दी जाती हैं और माओ का जय जयकार मनाया जाता है, इसके मानी क्या है ? आज किसकी जान, किस की इज्जत, किस का धन वहां पर सुरक्षित है ? कुछ भी सुरक्षित नहीं है । किसी का कुछ भरोसा नहीं है । इसी का क्या भरोसा है कि आप के साथ सुरक्षा व्यवस्था न रहे तो आप कलकत्ते घूम आएंगी सुरक्षित हो कर ? तो आज यह क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है कि नक्सलपंथी केवल जोतदार और भूमिहीन का झगड़ा लेकर नहीं आए हैं, वह झगड़ा तो है ही झगड़े के नाम पर उसकी आड़ में वे दूसरी आग लगा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप की ओर से, बंगाल सरकार की ओर से और हमारे सारे समाज की ओर से जिसमें हम भी शामिल हैं, उनके दुख-दर्द को दूर करने का अब तक काफी उपाय नहीं किया गया । जनता की सही शिकायतों को बहाना बना कर वह आगे बढ़ा रहे हैं । बल्कि यह कहिए कि वह उस चीज को ईंधन बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं । असली कारण तो दूसरा है । चीन आया हमारे ऊपर चोट करने 1962 में, मगर उसने देखा कि सारा देश एक हो गया । 1965 में चोट की पाकिस्तान ने । उसने देखा कि सारा देश एक हो गया । अब वह सोच रहे हैं कि ऐसा करो कि जिसमें देश एक न हो सके और उसके लिए एक ही उपाय है कि बीच बीच में झगड़े लगाओ, ऐसा इन्तजाम करो कि लोग लड़ते भिड़ते रहें और साथ ही साथ किसी के जान माल की सुरक्षा न रहे तो कोई किसी की परवाह नहीं करेगा । अभी उनके हिसाब से ठीक समय नहीं है । अब उनके हिसाब से सब ठीक हो जायगा तब उनको जो करना होगा वह करेंगे । इस बीच में वे हमसे फौजी लड़ाई क्यों करें, क्योंकि उनकी अगली सेना तो आगे बढ़ी हुई है । केवल बंगाल में ही नहीं, दूसरी जगहों में, भी, आन्ध्र में भी और बिहार में भी वह बढ़ते आ रहे हैं । मगर आप से हम यहां पार्टी के नाम पर नहीं, विरोधी पक्ष के हो कर नहीं, आप के प्रधान मंत्री होने की हैसियत से बहुत नम्रता से प्रार्थना करेंगे कि इस समय आप पार्टी को भूला कर देश की बात पर विचार कीजिए जो कि नहीं हो रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है कि आज आप अपने को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, उन दलों के साथ हाथ मिला कर चल रही हैं जो यह सब हथकंडे करा रहे हैं । इसके एक नहीं, हजार उदाहरण हैं । मैं सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने रखूंगी । एक उदाहरण तो यह है कि केरल में जो कुछ हुआ था 1959 में आज उससे दस गुना ही

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

नहीं, सौ गुना बंगाल में हो रहा है मगर उस समय 1959 में पंडित जवाहर लाल नेहरू को उतनी अकल नहीं थी जितनी आपको है। उस समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उतनी अकल न थी जो आज चव्हाण साहब को है और उन बुजुर्गों ने अपनी कम अकली से नम्बूद्रीपाद गवर्नमेंट को तोड दिया यह कह कर कि यह लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं और कांस्टीट्यूशन भंग हो गया है। आज यह उपद्रव उस समय से कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन चव्हाण साहब ने कभी यह नहीं माना कि कांस्टीट्यूशन भंग हो गया है। ला ऐंड आर्डर प्राबलम छोड़ कर और कोई बात ही नहीं वह मानते हैं। बराबर ला ऐंड आर्डर के बहाने पर बात को दबा देते हैं। न मालूम कितने काल अटेंशन हमने दिए, शार्ट नोटिस क्वेश्चंस दिए, एक नहीं आ पाया। कोई सवाल ही नहीं उठने पाता। कोई चर्चा ही नहीं होने पाती क्योंकि हम देखते हैं कि यहां आपकी सरकार टिकी हुई है तो कम्युनिस्ट दलों के बल पर टिकी हुई है और उसका एक नमूना मैं अभी आपको बताऊं। 6 तारीख को जब कि ऐडजर्नमेंट मोशन यहां पर आया था तो सी पी आई ने अपने दो आदमियों को छोड़ कर बाकी को भगा दिया, बाहर बैठा दिया जिससे कोई आपके खिलाफ वोट न कर सके। मगर सी पी एम ने आपके खिलाफ वोट किया और उसका नतीजा उन्हें मिला। एक हफ्ता दस दिन बाद एक छोटा सा चुनाव हुआ जिसमें एक ही जगह खाली थी जहां आप अपना कैंडीडेट खड़ा करते तो वह निर्विरोध चुना जाता ? मगर वह तो आप ने नहीं किया। आपके दल में लगता है जैसे कि कोई भी हरिजन नहीं कोई भी आदिम जाति का नहीं उस समिति के लिए आपने किसी को खड़ा ही नहीं किया और साथ ही साथ व्हिप निकाला कि सपोर्ट दि गवर्नमेंट स्टैंड और गवर्नमेंट स्टैंड लिखा नहीं जिससे किसी को मालूम न हो जाय। लिखित सबूत विरोधियों के हाथ लग जाये मगर सब को जबानी कह दिया कि सी पी एम के कैंडीडेट को सपोर्ट करो। तो यह कीमत आप दे रहे हैं। लेकिन यह समझ लीजिए कि किसी को आप खरीद नहीं पाती हैं। आप तो महज नौकर बनाती हैं। इसलिए हर महीने वेतन, मुशाहरा देना होगा, हर महीने कीमत देनी होगी। जिस दिन उनकी कीमत कम पहुंचेगी, तनख्वाह न मिलेगी, उस दिन वह आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश बड़ा है। अगर देश ही न रहा तो आप की गद्दी क्या रहेगी। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि आप उनकी मदद से पपेट गवर्नमेंट कठपुतली सरकार बनाने को राजी होंगी उनके हाथों में क्योंकि कल जो बातें चल रही थीं कि कम्बोडिया में सिहनोक तो उस वक्त निकाला गया जब कि वह अपनी गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बना हुआ था, उसके बाद विदेशों से फौजी मदद ले कर अपने ही देश को जीतने वह आ रहा है, अब यहां पर जो इशारा था उसके माने तो कुछ ऐसा ही लग रहा था लेकिन मैं नही मानने को तैयार हूं कि नेहरू की बेटी इस बात को मानेगी, यह कबूल करेगी, मगर उनका यह इशारा था, फिक्र न करो, अगर यह बदमाश तुम्हें हटा देंगे तो हम बाहर से फौजी मदद ले कर तुम्हें फिर गद्दी पर बिठा देंगे। मैं नहीं मानता कि नेहरू की बेटी के मन में यह बात आएगी या कभी आ सकती है। मगर उनकी ओर से तो इशारा कुछ ऐसा ही जान पड़ता था।

दूसरी बात यह है कि भीतर का जो बहुत बड़ा खतरा आया, वह आपके ही हाथों आया। आपने राष्ट्रपति पद के लिए अपने दल के उम्मीदवार का नामजदगी का पर्चा दाखिल किया, उसके बाद उसको हराने में कोई कोशिश उठा न रखी और जब वह हार गया तो बड़ी खुशी जाहिर की गई, बड़े जशन मनाये गये। इस सम्बन्ध में वर्किंग कमेटी में 25 अगस्त को जो प्रस्ताव पास हुआ उसकी सिर्फ तीन लाइन ही पढ़ूंगा—

"After hearing what the President has said, the Working Committee is of the

opinion that the allegations made...

MR. CHAIRMAN : Please try to be relevant. We are discussing the Finance Bill.

श्री मृत्युंजय प्रसाद : आज जनतन्त्र पर चोट हो रही है, इसलिये कह रहा हूं। फिनेन्स बिल पर देश की सभी बातें आया करती हैं, अगर आप को एतराज है तो नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : आप जरूर कहिये, मगर आप बहुत सीनियर आदमी हैं, थोड़ा रेलेवेंट कहिये।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : उस मीटिंग में यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें प्रधान मंत्री थी, बाबू जगजीवन राम थे, श्री फखरुद्दीन अली अहमद थे और उसमें पास हुआ—

"...the allegations against the President were on wrong assumptions based on information available at that time, and therefore they are untenable."

यानी आप लोगों ने कबूल कर लिया कि जो कुछ वहां आप लोगों ने किया था, वह अनटीनेबल था, गलत था, निराधार था, और यह आपने स्वीकार भी किया था क्योंकि वहां आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, उस प्रस्ताव के बिरुद्ध आपने वोट नहीं दिया था।

खैर, अब इस बात को जाने दीजिये। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ? जब बड़ी नाव डूबने लगती है तो आस-पास की छोटी नावों को भी खतरा बढ़ जाता है। आपकी पार्टी तो डूबी ही, लेकिन दूसरी पार्टिज में भी दरार पड़ गई, एक भी सुरक्षित न रह सकी एक बार कांग्रेस का झगड़ा आपने लगा दिया, तो अब तक वह कांग्रेस सोया नहीं है, चला आ रहा है चाहे जिस इलैक्शन को रोइये, जिसको चाहे कहिये, मगर कौन किसकी सुनता है।

अब मैं पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज पर आता हूं। बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं, लेकिन मैं दूर न जाकर आपकी बातों को लूंगा। यह आपकी ही किताब है। आपने कहा है कि पब्लिक सैक्टर के जस्टीफिकेशन में तीन बातें आती हैं—पहली चीज है—इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बनता है, दूसरी बात—ये उद्योग वहां पर कायम किये जाते हैं, जहां दूसरा कायम नहीं करना चाहता है और तीसरी बात है—इससे रिजनल इम्बैलेंस दूर होता है, सोशल गेन्ज होते हैं। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तो समझना या समझाना दोनों बड़ा मुश्किल है, जब तक आप उसकी डिटेल न बतलायें, इस लिये उसमें मैं इस समय नहीं जाऊंगा। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है कि जहां दूसरा नहीं करना चाहता, वहां आपने कायम किये हैं—ऐसा कौन सा बड़ा काम है, जो दूसरा नहीं कर रहा है और आपने पहले-पहल किया है। लोहे के कारखाने यहां पहले से कायम हैं। पिछले दिसम्बर में आपने रेलवे का जिक्र किया था—वह भी आपकी बनाई हुई नहीं है, पुरानी चीज है। मैं आज की ही एक ताजा खबर आपके सामने रखना चाहता हूं—आज ही आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है—लोहे में पर-इन्गाट-टन आप का क्या लागत खर्च पड़ता है ? आपने बतलाया है कि भिलाई में 1447 रु० टन, दुर्गापुर में 1726 रु० टन और रूरकेला में 2268 रु० टन, जब कि टिस्को में—उन्होंने दो कीमतें दी हैं—1275 रु० टन और 1156 रु० टन। आपके कारखानों में लेटेस्ट टेकनीक है, आपके कारखाने मोस्ट-मोडर्न हैं, लेकिन फिर भी आपके यहां कास्ट ज्यादा पड़ती है। अब जो सब से लेटेस्ट कारखाना बोकारो में आप बनाने जा रहे हैं, उसमें आपके अनुमान से ही 2500 रु० टन पड़ने वाला है—अब बतलाइये, इसमें कौन सा इन्फ्रा-स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है ?

अब जहां तक अदर-बेनिफिट्स का सवाल है—मैं कहना चाहता हूं कि आपने इन कामों से एम्पलायमेन्ट रोजी रोटी में कुछ नहीं बढ़ाया है, एम्पलायमेन्ट रोजी जितनी पहले थी अपनी जगह पर ही स्थित है, आप चाहें तो फिगर्स देख लें। इस समय मेरे पास सभी

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

आंकड़े मौजूद हैं किन्तु समय नहीं है, नहीं तो मैं उन फिगर्स को भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। आज आपके सभी कारखाने, दो-चार को छोड़ कर, लो-कैपेसिटी पर अपनी क्षमता से बहुत ही कम काम कर रहे हैं, उनके अन्दर आइडल-कैपेसिटी पड़ी हुई है, जिसका सब से बड़ा नुकसान यह होता है कि आदमी उनके अन्दर बेकार बैठा रहता है, जिससे उसकी आदत खराब हो जाती है, वहां के वर्क नार्म्स काम की मात्रा की अपेक्षा में हमेशा के लिये खराब हो जाती हैं, इस तरह से उस संस्था का भविष्य खराब हो जाता है।

आपने इधर एक और काम किया है—पता नहीं कब किया, कैसे किया, किससे सलाह ली? आप कहते हैं कि हम कहीं भी अपनी ओर से डिक्टेटोरियल एटीचूड नहीं रखते। आपके बजट में नहीं है, इस किताब में नहीं है, प्लान में नहीं है, लेकिन आप ने एक दम तीन लोहे के कारखाने कायम करने का वायदा कर लिया। बहुत अच्छा किया, इस बात से मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिये कि यह किसने तय किया, प्राइम मिनिस्टर ने तय किया या कैबिनेट ने तय किया, प्लानिंग कमीशन से कब पूछा गया? अचानक यह चीज कहां से आ गई और आ गई तो जब तक कोई स्कीम न बने, कोई प्लान न बने, किसी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पता न हो, जब तक आपने स्थान भी तय कर दिया, फलां प्रदेशों ही तक नहीं बल्कि फलां शहरों में इनको स्थापित किया जायगा। यह क्या है? यह पोलिटीकल डिसीज़न है, न कि इकानामिक डिसीज़न।

उधर आपने बोकारो स्टील लि० का चेयरमैन एक ऐसे आदमी को बना कर रखा है जो एक समय आप का सैक्रेटरी था और साथ साथ चेयरमैन भी रहा है। अब कहा जाता है कि वह इतना पुराना हो गया है कि उसके स्थान के लिये दूसरा आदमी नहीं मिलता है। पेंशन के बाद भी बहुत दिनों तक की रोजी लग गयी, काम चाहे हो या न हो। दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तान स्टील में, जो देश का सब से बड़ा संस्थान है, एक ऐसे आदमी को चेयरमैन बना रखा है, जो महज बैरिस्टर साहब हैं, क्या वहां कोई मुकदमा लड़वाना है। लोहे इस्पात का कोई अनुभव उन्हें नहीं था। क्या इसी तरह से बिजनेस चलेगा, इसी तरह से देश को उठायेंगे। इन सब चीजों से यही कहा जा सकता है—आपकी नीयत अच्छी है, मगर कुशलता नहीं है, प्रवीणता नहीं है, बनाना आता नहीं बनाना कुछ चाहते थे, बन गया कुछ और, फिर भी आप ज़िद के पक्के हैं कि हम बनायेंगे, ज़रूर बनायेंगे और उसी आदमी के हाथ में फिर आप सारे स्टील ट्रेड को दे रहे हैं। चलिये—डूबना तो है ही, क्योंकि यह तरीका काम को सम्भालने का नहीं है, जिसको कोई अनुभव नहीं था, उसको आपने चेयरमैन बना दिया। चार हज़ार रुपये महीना कोई कीमत नहीं रखता, जहां इतने करोड़ रुपयों की बात है। इधर बोकारो में जो आपकी कन्सल्टिंग-इन्जीनियरिंग फर्म है, वह कुछ कह रही है, आप कुछ कर रहे हैं, अगर वह नाकाबिल हैं तो उसको हटा दीजिये, मगर आपके चेयरमैन कहते हैं कि वह हिन्दुस्तान में सब से वेस्ट फर्म है। चेयरमैन कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता।

मैं यही कहना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर का काम ठीक से होना चाहिये। एक-दो जगह हुआ भी है, लेकिन भगवान की कृपा से हुआ है, आपकी दया से नहीं हुआ। बोकारो को ही ले लीजिये—कितने करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, कितना लग चुका है और पता नहीं कितना और लगेगा। बन जाने के बाद भी जब उसकी फुल प्रोडक्शन होगी, 4 मिलियन टन की प्रोडक्शन हो जाने के बाद अगर आपके ही अनुमान से लागत खर्च फी टन 2500 रु० होगा, तब उसका माल कहां बिकेगा? कौन खरीदेगा?

इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के बारे में आज ही जवाब में आपने कहा है—लोहे की चादरों, शीट्स की

कीमत 1967 में 960 रु० से 2500 रु० तक पहुंची थी। सन् 1968 में 990 और 3110 थी और 1970 में 2200 और 2150 हो गई। पहले सस्ती शीट्स 960, 950 और 860 तक थीं लेकिन आज उसकी कीमत 2450 और कम से कम 2200 तक है। तो कीमत बढ़ने का फायदा टाटा को हुआ। आप तो अपना घाटा पूरा करने के लिए दाम बढ़ा रही हैं लेकिन जो ज्यादा एफिशिएन्टली काम करते हैं वह उससे पैसा कमा रहे हैं। कहने के लिए तो यह गरीबों के लिए है लेकिन उन लोगों को फायदा हो रहा है।

15·51 hrs.

RE : INTERIM ORDER OF MADRAS HIGH COURT ABOUT ELECTION SYMBOLS

MR. CHAIRMAN: Shri R. Barua.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): Sir, this morning the Speaker has ordered that the Law Minister should make a statement. Now I think the Law Minister is not going to make any statement on the decision of the high court which is going to be flouted. Therefore, I request you to see that the statement is made just now, today.

MR. CHAIRMAN : The statement will be made tomorrow.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is wrong, because this decision was given by the high court. The interim order was given on the 30th and the election procedure was to have started yesterday. That was communicated on the 27th. And now, yesterday, after the decision of the High Court, the Election Commission has postponed everything. This is a conspiracy which must not be allowed to materialise. Therefore, I request that you should see that a statement is made today. Why is it going to be made tomorrow? Because they want to do further damage to the cause. There is nothing to be collected from Trivandrum, because everything is here available in the Election Commission's office. Why is it going to be made tomorrow? Therefore, I would request you to direct them that the statement must be made today.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): I contacted the Law Minister, and I pointed out to him the anxiety of the House that he should make a statement. He said this is not an order passed by the Ministry; it is passed outside. He is going to enquire and he would be able to give full information only tomorrow. I have twice telephoned to him. He said he is anxious to do it, but he is unable to do it today.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is not the correct procedure. He has already got the cause of the Pradesh Committee damaged so heavily that it is not going to be repaird. If they take more time, I do not know what is going to happen. Therefore, he should not be allowed to consume one more day, because if they flout the high court's interim order.... (*Interruption*).

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : The Minister of Parliamentary Affairs says that the Law Minister was anxious to make the statement but that he has not been able to get the full information which he wanted to get.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is available to him. The Law Minister is hiding the facts. A conspiracy is going on.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : He need not go to America to get the information. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Anyway, your sentiments will be conveyed to them. Both the Prime Minister and the Minister of Parliamentary Affairs have heard what you have said.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is wrong. (*Interruption*)

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha) : Sir, you should satisfy yourself: why they could not get information which is here in the Election Commission's office itself. Why not get the information? (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Bajaj, Mr. Naidu, your leader has spoken.